

न्यूज़ ब्रीफ

जापान टूरिज्म एक्सपो में भागीदारी करेगा यूपी

अमृत विचार, लखनऊ : जापान के टोकियोमें शहर में गुरुवार से शुरू होने वाले जापान टूरिज्म एक्सपो 2025 में प्रदेश की बौद्ध विरासत, प्रमुख तीर्थ स्थल, व्यंजन और हस्तशिल्प आदि दिखेंगे। यूपी पर्यटन, पर्वेलियन एक्सपो में आगंतुकों को राज्य की सांस्कृतिक विविधिता और धार्मिक विरासत से अवगत कराएगा। यह जानकारी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को जारी बयान में दी। उन्होंने बताया कि टोकियोमें शहर स्थित आइवी स्काई एक्सपो में 25 से 28 सितंबर तक आयोजित होगा। जापान में बौद्ध धर्मावलंबी बहुतायत है। ऐसे आयोजनों से प्रदेश की आध्यात्मिक पर्यटन को विशिष्ट पहचान मिलेगी। इस आयोजन में चीन, संप्रदाय अधिकारी और पर्यटन उद्योग के साझेदार आदि का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा।

निजीकरण की गोपनीय योजना का आरोप

अमृत विचार, लखनऊ : विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों का आरोप है कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ मिलकर ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण की 'गोपनीय योजना' तैयार कर रहे हैं। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि फिक्ट भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की तैयारी शुरू की जाएगी। संघर्ष समिति ने जानकारी साझा की कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के निदेशक जनरल आलोक कुमार ने 9 सितंबर देश के सभी ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि फेडरेशन और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियर्स इस मामले को केंद्रीय विद्युत मंत्री के सामने शीघ्र रखेंगी।

पीडीए की जनचेतना पूरे देश में फैली : अखिलेश

अमृत विचार, लखनऊ : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अा. से जन्मी पीडीए की जनचेतना अब पूरे देश के 'पीड़ित, दुखी, अपमानित' समाज के लिए अपने सम्मान, अधिकार, आरक्षण, पिछड़ेपन के दंश व दमित स्तर से उबरने के लिए संघर्ष की नयी आवाज बन गयी है। जो लोग जहां भी संख्या में कम हैं, वो भी जान गये हैं कि एकजुटता की शक्ति ही उनकी संख्या की कमी की क्षतिपूर्ति करने में सक्षम होगी। सपा प्रमुख ने जारी बयान में कहा कि पीडीए उन अंतिम लोगों के स्वाभिमान-स्वमान के नवजागरण का नाम है, जिनके हिस्से ऐतिहासिक रूप से उपेक्षा और उत्पीड़न ही आया है। इसीलिए 'जो पीड़ित वो पीडीए' के संझांतिक सूत्र से एक-सूत्र हुए पीडीए समाज ने एक साथ मिलकर अब ये संकल्प उठाया है कि पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे।

सरकार को सुझाव देने में

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश अभियान में सरकार को सुझाव देने में ग्रामीण आगे हैं, जबकि इनके मुकाबले शहरी फिलहाल पीछे हैं। ग्रामीण इलाकों से अब तक सर्वाधिक 4.70 लाख और नगरीय क्षेत्रों से 1.30 लाख सुझाव मिले हैं। लगभग 6 लाख प्रदेशवासियों ने अपने-अपने सुझाव साझा किए हैं जिनमें 31—60 आयु वर्ग वाले ज्यादा हैं।

दरअसल, विकसित उत्तर प्रदेश अभियान के तहत बुधवार 24 सितंबर तक लगभग 6 लाख प्रदेशवासियों ने अपने सुझाव साझा किए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों

जीसटी में सुधार से स्वदेशी उद्योग को मिलेगा बढ़ावा : रालोद

लखनऊ में व्यापारियों से संवाद करते रालोद महासचिव अनिल दुबे व अन्य।

अमृत विचार, लखनऊ : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी करने का निर्णय एक देश-एक कर की नीति को मजबूती प्रदान करता है और देश की कर प्रणाली को और सरल एवं पारदर्शी बनाता है। इससे स्वदेशी उद्योगों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। यह बात रालोद व्यापार

सरकारी अस्पतालों में अपग्रेड हुई सेवाएं : ब्रजेश पाठक

500 करोड़ की लागत वाली 84 स्वास्थ्य इकाइयों का उप मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण व शिलान्यास

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि वर्ष 2017 के बाद से हमारी सरकार ने सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीनें स्थापित कर अपग्रेड किया है। चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ सभी अस्पतालों में मैन पावर की संख्या बढ़ी है।

उप मुख्यमंत्री बुधवार को इंदिरा नगर स्थित राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (ट्रेनिंग सेंटर) में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की 500 करोड़ रुपये मूल्य की 84 नवीन स्वास्थ्य इकाइयों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने के



लखनऊ में लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान उपस्थित उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व अन्य।

बाद संबोधित कर रहे थे।

इन जिलों में हुआ शिलान्यास एवं लोकार्पण : लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, गाजीपुर,

कौशाम्बी, बस्ती, मुजफ्फर नगर, अयोध्या, अलीगढ़, गोंडा, बागपथ, बलरामपुर, हाथरस, बदायूं, जालौन, एटा, मऊ, बलिया, भदोही,

कानपुर नगर, मिर्जापुर, श्रावस्ती, बहराइच, रामपुर, बिजनौर, संभल, चंदौसी, कुशीनगर, महाराजगंज, अमरोहा, गाजीपुर, फतेहपुर,

मानसून की विदाई की शुरुआत

अमृत विचार, लखनऊ : उत्तर प्रदेश से मानसून अब धीरे-धीरे विदा होने की ओर है। बिहार से सटे कुछ जिलों में बुधवार को हल्की बूंदबांदी हुई है। लखनऊ में दो दिन बाद बूंदबांदी की संभावना जताई जा रही है। राजधानी में आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया है, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा है।

मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एम दानिश ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बुधवार से वापसी की शुरुआत हो गई है। यानी कि प्रदेश के पश्चिमी भाग से मानसून वापस जा चुका है। उन्होंने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने 17 सितंबर की अपनी सामान्य लिथि के सापेक्ष तीन दिन पूर्व 14 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से वापसी शुरू कर दी थी। बुधवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों समेत उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों से मानसून वापस लौट गया है, लेकिन बिहार से सटे जिलों में बुधवार को बूंदबांदी हुई है।



● कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी करेंगे 4 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को लाभान्वित

लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मार्गदर्शन लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मिलकर व्यापक रणनीति बनाई। यही कारण है कि इस बार छात्रवृत्ति का लाभ छात्रों तक नवरात्र के पावन अवसर पर पहुंचेगा।

इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप, समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण, राज्य मंत्री समाज कल्याण संजीव गोंड और अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसार मौजूद रहेंगे।

विकसित भारत बनने में एनीमिया बड़ा अवरोध : अमित घोष

अमृत विचार, लखनऊ : प्रदेश में 46 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं के एनीमिक होने पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित घोष ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब हम 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की बात करते हैं तो एनीमिया इसमें बड़ा अवरोधक है। इस समस्या को खत्म करने के लिए तीन प्रतिशत दर प्रतिवर्ष कम करने का लक्ष्य रखा

एनिमिया पर वार, मिलकर करेंगे 12 के पार एनीमिया प्रदेशव्यापी जटिल समस्या से पार पाने के लिए एक प्लेटफार्म पर जमा हुए विभागों के प्रमुख व विशेषज्ञों ने मथन किया और नतीजे पर पहुंचे कि महिला शिक्षक, महिला प्रधान, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं व अगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की नेतृत्व क्षमता बढ़ाकर समुदाय में एनीमिया के प्रति महिलाओं को सजग किया जाए। शायद ली गई कि मिलकर करेंगे हीमोग्लोबिन 12 के पार।

गया है, उसे प्राप्त करने के लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे। प्रमुख सचिव बुधवार को हजरतगंज

स्थित होटल में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, केजीएमयू व सेंटर ऑफ एडवोकेसी

योगी ने यूपी ट्रेड शो की तैयारी का किया निरीक्षण

अमृत विचार, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा स्थित इण्डिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टॉल व प्रदर्शनी से लेकर देशी-विदेशी आगन्तुकों के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखा और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की सहभागिता के दृष्टिगत सुरक्षा के निर्देश देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

डिजिटल क्रॉप सर्वे 10 अक्टूबर तक करें पूरा

अमृत विचार, लखनऊ : मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव ने डिजिटल क्रॉप सर्वे के सचिव में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिलों को यह कार्य 10 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वे के कार्य में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त मैनपावर लगाई जा सकती है और लेखपालों का सहयोग भी लिया जाए। साथ ही, सर्वे के साथ-साथ सत्यापन (वैरिफिकेशन) के कार्य में भी प्रगति सुनिश्चित की जाए।

गिरिजा शंकर अध्यक्ष, गिरीश मिश्र बने महामंत्री

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार : उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव चारबाग बस स्टेशन, लखनऊ में हुआ। प्रदेश भर की 200 से अधिक प्राथमिक इकाइयों, 20 क्षेत्रीय इकाइयों और विशिष्ट इकाइयों के प्रतिनिधियों ने इस चुनाव में हिस्सा लिया। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी चुनाव अधिकारी घनश्याम यादव महासचिव, उप्र राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने की।

सभा में गिरिजा शंकर तिवारी को लगातार दूसरी बार प्रांतीय अध्यक्ष और गिरीश चंद्र मिश्र को 12वीं बार प्रांतीय महामंत्री पद पर निर्विरोध चुना गया। इस अवसर पर निगम

31 अस्पतालों में स्थापित होंगे आधुनिक उपकरण

अमृत विचार, लखनऊ : उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को उच्चो्कृत किया जा रहा है, उवत क्रम में ही प्रदेश के 31 अस्पतालों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इसके लिए 10.74 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

संतकबीर नगर, प्रतापगढ़, सीतापुर, आजमगढ़, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, उन्नाव, कानपुर देहात, बांदा, सिद्धार्थ नगर, शामली, हापुड़, रायबरेली, जौनपुर, मथुरा, मैनपुरी।

शिशु बुद्धि से जीएसटी सुधार नहीं समझा जा सकता : सुधांशु त्रिवेदी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जीएसटी रिफार्म फैसले को ऐतिहासिक

बताते हुए विपक्ष पर यह कह कर कटाक्ष किया कि इस बदलाव को समझने के लिए शिशु बुद्धि से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसी कुशाग्र बुद्धि चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कदम किसी तात्कालिक राजनीति निर्णय का नतीजा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टि का हिस्सा है।

● कहा- यह कदम किसी तात्कालिक राजनीति निर्णय का नतीजा नहीं बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टि का हिस्सा है

बुधवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफार्म को अमल में लाकर आम उपभोक्ताओं मध्यमवर्गी लोगों, व्यापारियों और राष्ट्र के हितों को सुरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और आमजन का हितेषी बनाना है।

त्रिवेदी ने जीएसटी स्लैब में किए गए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि नए स्लैब लागू होने के बाद आम जनता को जरूरी

स्तूपनुमा भवन बनाकर रखे जाएं बुद्ध के अवशेष

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सिद्धार्थनगर स्थित पिपरहवा (कपिलवस्तु) में भगवान बुद्ध की अस्थि मंजूषा एवं अन्य अवशेषों को संरक्षित करने के लिए एक स्तूपनुमा भवन बनाए जाने का अनुरोध किया है। साथ ही अवगत कराया कि इस कार्य के लिए भूमि उपलब्ध है।

यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि पिपरहवा वही स्थान है, जहां 1898 में ब्रिटिश इंजीनियर क्लैक्स्टन

● कपिलवस्तु के पिपरहवा में भवन बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

पेपे को उत्खनन के दौरान बुद्ध के अवशेष, बहुमूल्य रत्न एवं पालि भाषा में लिखी स्वर्ण पटिका प्राप्त हुई थी। यह रत्न भंडार हाल ही में हांगकांग की नीलामी से भारत लाया गया है। उन्होंने कहा कि यहां स्तूपनुमा भवन बनने से न केवल देश-विदेश से बौद्ध श्रद्धालु आकर्षित होंगे बल्कि स्थानीय पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। बुद्ध कपिलवस्तु में पले-बढ़े और अपने जीवन के पहले 29 वर्ष यहीं रहे।

विपक्षी नेताओं को भी देखा गाड़ियां टीवी, फ्रिज खरीदते : ब्रजेश पाठक



लखनऊ के आलमबाग बाजार में एक दुकान पर व्यापारी से जीसटी सुधार को लेकर संवाद करते सुधांशु त्रिवेदी, ब्रजेश पाठक व आनंद द्विवेदी। अमृत विचार

अमृत विचार : जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत बुधवार को राज्यसभा सांसद, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने कार्यकर्ताओं के साथ चंदर नगर मार्केट आलमबाग में पदयात्रा करके व्यापारियों व उपभोक्ताओं से संपर्क व संवाद किया। दुकानों में जाकर जीएसटी लाभ के स्ट्रीकर लगाए और व्यापारियों को गुलाब भेंट दिया। स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए सभी से आह्वान किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि मैंने कल से ढेर सारे विपक्षी नेताओं को देखा है गाड़ियों के शोरूम में गाड़ियां खरीदते हुए, टीवी, फ्रिज खरीदते हुए, वह भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। व्यापारियों से संपर्क के दौरान मानसिंह, महानगर उपाध्यक्ष अशोक तिवारी, मीडिया प्रभारी धीरवीर गर्ग, अभिषेक खरे, विनायक पांडे, पीयूष दीवान, मंडल अध्यक्ष राजन वर्मा, महेंद्र राजपूत, मानस बाहरी, रूपा देवी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सामान पर बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि सीमेंट और लोहे-स्टील पर टैक्स की दरों को कम करने के फैसले से घर बनाने की लागत में भी कमी आएगी। उन्होंने



उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के चुनाव में विजयी सदस्य।

● रोडवेज परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी के चुनाव में महामंत्री 12वीं बार निर्विरोध निर्वाचित

महासंघ के अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों में रविन्द्र कुमार

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अरविन्द्र कुरील, गुलजार अहमद, महेश कुमार रांय, सुरेश चन्द्र पांडेय उपाध्यक्ष, संजय कुमार राणा अपर महामंत्री, चन्द्र हंस, सुरेश चन्द्र मिश्र, विवेकानंद सिन्हा, सतीश कुमार उप महामंत्री, बीके शुक्ल कोषाध्यक्ष, धर्मेन्द्र सिंह संगठन मंत्री और वेदरत्न

वर्मा प्रचार व सांस्कृतिक मंत्री शामिल हैं। साथ ही 42 सदस्यीय कार्यकारिणी भी सर्वसम्मति से निर्विरोध चुनी गई। घनश्याम यादव ने बताया कि चुनाव में प्रतिनिधियों का जोश व भागीदारी उल्लेखनीय रही और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हुई।

मुकदमा लड़कर अभ्यर्थियों ने लिया था उत्तर कुंजी देखने का अधिकार

लोकसेवा आयोग की चक्की में पिस रहे प्रतियोगी छात्र

तीन वर्ष जारी हुई उत्तर कुंजी

न्यायालय में हलफनामा देकर भी आयोग अपनी बात से मुकर गया था। हमलोग ने कंपटीशन देने वाले छात्रों का संगठन प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति बनाया और फिर से न्यायालय गए। जिसके बाद पीसीएस 2015, 2016, 2017 की उत्तर कुंजी जारी हुई। सभी में प्रश्नों के गलत उत्तर रखे जाने के कारण उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया गया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय पर रोक लगा दी थी।

विकल्प विवादित या गलत होने का आरोप अभ्यर्थी लगाते थे। कई बार किसी प्रश्न का उत्तर आयोग जिसे सही मानता, उसे प्रतियोगी छात्र या पुस्तकें सही नहीं मानती थी। लेकिन परिणाम आयोग अपने अनुसार जारी कर देता था। इसे लेकर प्रतियोगी छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया था

और न्यायालय की शरण में जाना पड़ा था।

इसी मामले को लेकर न्यायालय ने आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष को तलब भी किया था। याचिकाकर्ता रहे अवनीश पाण्डेय बताते हैं कि इसके बाद आयोग ने न्यायालय से बचने के लिए 7 सदस्यों की कमेटे बनाई।

जायेगी। दोनों आख्या समितियों में अंतर होने पर तीसरी एक्सपर्ट कमेटे गठित कर विवादित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद संशोधित उत्तर कुंजी प्रांरिक परीक्षा के परिणाम घोषित करते समय ही जारी किया जाएगा। इसके बाद भी आयोग उत्तर कुंजी नहीं जारी किया।



कांग्रेस ने सहयोगियों से झाड़विंग सीट लेने को बुलाई सीडब्ल्यूसी बैठक : भाजपा - 5



देश को अमेरिका के साथ ऊर्जा व्यापार बढ़ने की उम्मीद : वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल - 8



एक ही बाजार पर निर्भर न रहे ग्लोबल साउथ निष्पक्ष आर्थिक व्यवस्था बनाए - 9



हार्दिक पंड्या ने टी-20 रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा- 10

आज का मौसम

34.0°

अधिकतम तापमान

24.0°

व्यूनतम तापमान

सूर्योदय

06.02

सूर्यास्त

06.05

ब्रीफ न्यूज

कन्नड़ उपन्यासकार भैरप्पा का निधन

बेंगलुरु। लोकप्रिय कन्नड़ उपन्यासकार एवं दार्शनिक एसएल भैरप्पा का बुधवार को यहां एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। राष्ट्रीयान अस्पताल ने कहा कि महान भारतीय उपन्यासकार, दार्शनिक, पद्म श्री, पद्मभूषण और सरस्वती सम्मान से सम्मानित एसएल भैरप्पा को आज अपराह्न 2:38 बजे दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। भैरप्पा लोकप्रिय उन्प्यासों वंशवृक्ष, दातू, पर्व, मंदरा आदि के लिए जाने जाते हैं।

सीडीएस का कार्यकाल 30 मई तक बढ़ाया

नई दिल्ली। सरकार ने रक्षा क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल अगले वर्ष 30 मई तक बढ़ा दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने जनरल चौहान का कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जनरल चौहान 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। उन्हें देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की एक दुर्घटना में मौत के बाद 28 सितंबर 2022 को सीडीएस नियुक्त किया गया था।

अंतर्राज्यीय हथियार गिरोह का भंडाफोड़

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक अवैध हथियार और गोला-बारुद गिरोह का भंडाफोड़ कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया। दो सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल, पांच सिंगल-शॉट पिस्तौल और 210 कारतूस बरामद किए गए। यूपी के मुरादाबाद में कारतूस निर्माण फैक्ट्री भी पकड़ी। जहां से कार्टा माल, कारतूस बनाने के उपकरण 257 कारतूस, बारुद जब्त की गई।

सोनू सूद से सात घंटे ईडी ने की पूछताछ

नई दिल्ली। अभिनेता सोनू सूद से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को ऑनलाइन स्टूड्योबी एप ‘वन एस बेट’ से जुड़े धन शोधन मामले में सात घंटे तक पूछताछ की। सोनू सूद (52) दोपहर 12 बजे मध्य दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे और शाम सात बजे बाहर निकले। ईडी ने उनका बयान दर्ज कर लिया है। ईडी की जांच ऑनलाइन स्टूड्योबी मंच वन एक्स बेट के संभालन से संबंधित है, जिस पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और कर चोरी का आरोप है। यह एन कुरासाओ में पंजीकृत है।

निवेश, नवाचार और संस्कृति के महाकुंभ का आज होगा आगाज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ/ ग्रेटर नोएडा

अमृत विचार : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) के तीसरे संस्करण की शुरुआत करेंगे। 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने जा रहे यूपीआईटीएस में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार क्षमताओं का भव्य प्रदर्शन होगा। इस मेगा आयोजन का उद्देश्य केवल निवेश और व्यापार को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर स्थापित करना और युवाओं, उद्यमियों व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए स्म्यूचर-रेडी प्लेटफॉर्म तैयार करना भी है। इस बार 2500 से अधिक प्रदर्शक, 500 विदेशी खरीदार और 5 लाख से अधिक विजिटर्स के आने की उम्मीद है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) पवेलियन 343 स्टॉल्ल्स के माध्यम से हर जिले के सिग्नेचर प्रोडक्ट्स को पेश करेगा। भदोही का कालीन, फिरोजाबाद का ग्लासवर्क, मुरादाबाद का मेटलवेयर और सहारनपुर की नक्काशी जैसे उत्पाद लोकल से ग्लोबल की यात्रा को नई दिशा देंगे। यूपीआईटीएस में न केवल व्यापार का मंच होगा, बल्कि

- **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे यूपीआईटीएस की शुरुआत**
- **2500 से अधिक प्रदर्शक, 500 विदेशी खरीदार आने की उम्मीद**

रुस-इंडिया बिजनेस डायलॉग से मिलेंगे नए अवसर
लखनऊ। इस बार रुस आयोजन के साथ बतौर पार्टनर कंट्री सम्मिलित हो रहा है। 26 सितंबर को रुस-इंडिया बिजनेस डायलॉग आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत और रुस के उद्योगपतियों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, शिक्षा क्षेत्र और सरकारी नीति-निर्माताओं के लिए साझा मंच उपलब्ध होगा। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, तकनीकी साझेदारी और संयुक्त उपक्रमों को प्रोत्साहित करने का यह अवसर उत्तर प्रदेश के उद्योगों और कारोबारियों के लिए नई संभावनाएं खोलेगा।

उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का भी जीवंत प्रदर्शन करेगा। आगंतुक भोजपुरी, अवधी, बुंदेली और थारू लोक परंपराओं के रंगीन प्रदर्शन के साथ सूफी गायन, कथक नृत्य और सुगम संगीत का भी आनंद लेंगे।

लद्दाख में हिंसक झड़पों में 4 की मौत 40 पुलिसकर्मियों सहित 80 घायल

राज्य का दर्जा मांग रहे प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय में की तोड़फोड़

- **स्थिति संभालने को पुलिस को करनी पड़ी फायरिंग, लेह में निषेधाज्ञा लागू**

लेह, एजेंसी

लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बुधवार को यहां जारी आंदोलन हिंसक हो गया। इस दौरान सड़कों पर आगजनी और झड़पें हुईं, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 40 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 80 लोग घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

बुधवार सुबह की शुरुआत लद्दाख की राजधानी लेह में पूर्ण बंद के साथ हुई। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, फर्नीचर तोड़ दिए गए, कागजातों में आग लगा दी गई। कई वाहनों को भी आग आग के हवाले कर दिया गया। राजधानी लेह में पूर्ण बंद के बीच आग की लपटें और काला धुआं देखा जा सकता था। प्रदर्शनकारियों द्वारा व्यापक हिंसा शुरू करने के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए

छात्राओं का यौन उत्पीड़न, धर्मगुरु पर मामला दर्ज

- **दिल्ली स्थित श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान का संचालक रहा है चैतन्यानंद**

नई दिल्ली, एजेंसी

कभी प्रतिष्ठित धार्मिक संगठन से जुड़े रहे एक स्वयंभू धर्मगुरु पर यहां एक प्रबंधन संस्थान की कई छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी फरार है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी दक्षिण-पश्चिम दिल्ली स्थित श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान में संचालक हैं। पुलिस को संस्थान से नकली राजनयिक नंबर प्लेट वाली वोल्वो कार भी मिली, जिसका इस्तेमाल सरस्वती करता था। उसके खिलाफ

लुक आउट नोटिस जारी, पांच राज्यों में छापेमारी

दिल्ली पुलिस स्वामी चैतन्यानंद की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है, ताकि वह देश छोड़कर भाग न सके। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में पुलिस की टीमें बाबा की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। यह कार्रवाई पीड़ित छात्राओं के गंभीर आरोपों के बाद शुरू की गई है। छात्राओं का कहना है कि चैतन्यानंद उन्हें नंबर कम करने और फेल करने की धमकी देकर अपने कमरे में बुलाता था। जगदगुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणाम्नाथ श्री शारदा पीठम, श्रीोरी ने खुद को चैतन्यानंद सरस्वती से अलग कर लिया है। इससे पहले सरस्वती इसी पीठ से जुड़ा था।

2009 में डिफेंस कॉलोनी थाने में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था, जबकि 2016 में वसंत कुंज थाने में छेड़छाड़ की एक और शिकायत दर्ज की गई थी। ताजा मामले में शिकायत चार अगस्त को वसंत कुंज उत्तर थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान में पीजीडीएम कर रही 32 छात्राओं के बयान

दर्ज किए। इनमें से 17 ने आरोप लगाया कि सरस्वती ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, अश्लील संदेश भेजे। संस्थान में कार्यरत तीन महिलाओं पर छात्राओं पर उसकी मांगें मानने के लिए एबसे डालने का आरोप है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और बाद में 16 पीड़ितों ने मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी।

● मामले तत्काल सूचीबद्ध करने की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूट

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने बुधवार को कहा कि वह उस समय तक किसी मामले को उसी दिन तत्काल सूचीबद्ध करने का आदेश नहीं देंगे, जब तक कि किसी को फांसी न दी जा रही हो। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या कोई न्यायाधीशों की स्थिति समझता है और यह जानता है कि वे कितने घंटे काम करते हैं तथा कितने घंटे सो पाते हैं। न्यायमूर्ति कांत उस पीठ का नेतृत्व कर रहे थे, जो तत्काल सुनवाई के लिए मामलों को

पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों का सहयोगी गिरफ्तार

श्रीनगर। पुलिस ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर से मोहम्मद यूसुफ कटारी (26) को गिरफ्तार किया जिसने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान की थी। श्रीनगर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले से गिरफ्तारी की। उसकी पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को रसद प्रदान करने में भूमिका थी। इन आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव में डेर कर दिया गया था। सेना के विशिष्ट पैरा कमांडो ने 29 जुलाई को मुठभेड़ में श्रीनगर के बाहरी इलाके में तीन आतंकियों को मार गिराया था। जिनमें सुलेमान उर्फ आसिफ भी शामिल था, जिसे 22 अप्रैल के पहलगाम हमले का भी मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है।

एक सम्पूर्ण दैनिक अखबार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस समेत 94,916 करोड़ रुपये की छह परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। जिसमें बिहार में रेलवे दोहरीकरण, फोर लोन सड़क निर्माण के अलावा देश में जहाज निर्माण एवं समुद्री विकास, सीएसआईआर योजना की स्वीकृति के साथ चिकित्सकीय शिक्षा को विस्तार देना शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 10.9 लाख रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी है।

सरकार की ओर से कहा गया कि कुल बोनस राशि 1,886 करोड़ रुपये है। यह बोनस 10,91,146 रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए स्वीकृत किया गया है। पात्र रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) का भुगतान प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा और दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है।

सीबीएसई कक्षा 10 12 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से होंगी

नई दिल्ली। सीबीएसई अगले साल 17 फरवरी से कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा। अधिकारियों ने बुधवार को यह घोषणा की। बोर्ड ने महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए अस्थायी डेटशीट की घोषणा की। यह पहली बार है कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं एक शैक्षणिक सत्र में दो बार आयोजित की जाएंगी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि पहला संस्करण 17 फरवरी से छह मार्च, 2026 तक जबकि दूसरा संस्करण 15 मई से एक जून तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से नौ अप्रैल, 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

उसी दिन सुनवाई तब, जब मामला फांसी का हो

नई दिल्ली, एजेंसी

● मामले तत्काल सूचीबद्ध करने की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूट

सूचीबद्ध करने पर सुनवाई करते हैं। न्यायमूर्ति कांत ने यह टिप्पणी उस समय की, जब अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने उल्लेख किया कि राजस्थान में एक आवासीय मकान की आज नीलामी होगी और इसलिए मामले को आज ही सूचीबद्ध किया जाए। इस पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि जब तक किसी को फांसी नहीं होने वाली हो, मैं किसी भी मामले को उसी दिन सूचीबद्ध नहीं करूंगा।

आईआईटी रुड़की ने किया अमृता विश्व विद्यापीठम एवं स्वीडन के उस्पाला विवि के साथ अध्ययन

- **पुरातन सभ्यताओं को रही है प्रकृति और स्थायित्व की गहरी समझ**



देशांतर रेखा के आसपास स्थित शिव शक्ति अक्ष रेखा पर पाए गए। उपग्रह डेटा और पर्यावरणीय विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि यह संरेखण जल संसाधन उपलब्धता, कृषि उपज और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से समृद्ध क्षेत्रों में हैं।

रेलवे के 10.9 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस, छह प्रोजेक्ट मंजूर

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसले

- नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में जहाज निर्माण और समुद्री वहन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के व्यापक पैकेज को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह पहल रोजगार सृजन और निवेश को प्रोत्साहन देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और अपूर्ति शृंखलाओं को लचीला बनाने में भी मददगार होगी। इस पैकेज को चार स्तंभों पर आधारित किया गया है। इसके तहत घरेलू

जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाने, दीर्घकालिक वित्तपोषण की सुविधा, नई एवं पुरानी जहाज निर्माण परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहन, तकनीकी क्षमताओं एवं कोशल विकास को बढ़ावा देने के साथ नीतिगत सुधार भी लागू किए जाएंगे।

जहाज निर्माण, समुद्री विकास को 69,725 करोड़

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा केंद्रीय और राज्य सरकार के विकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ और उन्नत करने के लिए 5,000 स्नातकोत्तर (पीजी) सीट बढ़ाने की योजना के तीसरे चरण को बुधवार को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को उन्नत करने के वास्ते 5,023 एमबीबीएस सीट बढ़ाने के लिए केंद्रीय योजना के विस्तार को भी मंजूरी दी गई। इस पहल से स्नातक चिकित्सा क्षमता में वृद्धि होगी, अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीट सृजित करके विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी।

एमबीबीएस और पीजी में सीटों को बढ़ाने पर मुहर

अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट फेलोशिप के लिए 2,277 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी और थापा एवं संगोष्ठी के माध्यम से ज्ञान को साझा करने को बढ़ावा दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में, 15वें वित्त आयोग के चक्र 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 2,277.397 करोड़ के परियचय के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की क्षमता निर्माण को मंजूरी दी गई।

सीएसआईआर की 2,277 करोड़ की योजना स्वीकृत

अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट फेलोशिप के लिए 2,277 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी और थापा एवं संगोष्ठी के माध्यम से ज्ञान को साझा करने को बढ़ावा दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में, 15वें वित्त आयोग के चक्र 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 2,277.397 करोड़ के परियचय के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की क्षमता निर्माण को मंजूरी दी गई।

नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार ने दी बाजार को ताकत : मुख्यमंत्री



लखनऊ के हजरतगंज में बुधवार को एक दुकान पर रिस्टर लगाते मुख्यमंत्री योगी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : जीएसटी सुधार से सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के व्यापारियों, ग्राहकों को मिलने का रहा है। इस घोषणा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि नवरात्रि के पहले दिन से लागू हुए नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार ने बाजार में नई ऊर्जा भर दी है। योगी ने बताया कि जीवन रक्षक 33 दवाएं जीएसटी से मुक्त कर दी गई हैं, वहीं नोटबुक-पेंसिल पर जीएसटी शून्य हो जाने से विद्यार्थियों की पढ़ाई भी सस्ती हुई है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को हजरतगंज स्थित यूनिवर्सल बुकसेलर के पास पत्रकारों से बातचीत में कहा कि घटे जीएसटी दरों से आम उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिल रहा है। इस सुधार ने जहां उपभोक्ताओं को राहत दी है, वहीं बाजार की मजबूती और रोजगार सृजन का मार्ग भी प्रशस्त किया है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्रियों

को जीरो या पांच प्रतिशत के दायरे में लाया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, बाजार में खपत बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि हुई है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं। मुख्यमंत्री ने हजरतगंज मार्केट में व्यापारियों और उपभोक्ताओं से मुलाकात की। जीएसटी सुधार से संबंधित पंपलेट और बैनर वितरित किए।

देश का जीएसटी संग्रह 22 लाख करोड़ रुपये पहुंचा

मुख्यमंत्री के अनुसार, यूपी देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है और इस सुधार से यहां की अर्थव्यवस्था को विशेष मजबूती मिलेगी। सीएम ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद देश का कलेक्शन सात लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा है। जबकि यूपी में यह 49 हजार करोड़ से 1.15 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुका है।

विरासत और जलवायु के बीच बने सेतु

सह-अन्वेषक प्रो. थंगा राज वेंकिया ने इसे एक उल्लेखनीय अंत-विषय सहयोग बताया, जो विरासत और जलवायु लचीलेपन के बीच सेतु का काम करता है। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार, यह निष्कर्ष दर्शाते हैं कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर में गणनीतिक पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि निहित है, जिसे आज सतत विकास और जलवायु चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए पुनः लागू किया जा सकता है।

मुख्य अन्वेषक प्रो. के.एस. काशीविश्वनाथन (डब्ल्यूआरडीएम विभाग, आईआईटी रुड़की) ने कहा कि यह शोध दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यताओं को प्रकृति एवं स्थायित्व की गहरी समझ रही होगी, जिसने मंदिर निर्माण के स्थान

चयन में मार्गदर्शन दिया। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. कमल किशोर पंत ने कहा कि यह अध्ययन इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं।

तृतीय चंद्रघंटा



मां दुर्गा की तीसरी शक्ति हैं चंद्रघंटा। नवरात्र में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा-आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। देवी चंद्रघण्टा पूजा से शुक्र ग्रह का प्रभाव बढ़ता है।

बीज मंत्र...ऐं श्रीं शक्तयै नमः।

न्यूज ब्रीफ

उत्तराखंड के कुछ हिस्सों से विदा हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून

देहरादून, अमृत विचार : उत्तराखंड में कहर बरपाने के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून बुधवार को प्रदेश के कुछ भागों से विदा हो गया। वहीं, अगले 2-3 दिनों में उत्तराखंड के कुछ और भागों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो चली हैं। मानसून की वापसी की रेखा अब रामपुर, बुलंदशहर हरिद्वार, एटा, बांसवाड़ा, वाराणसी, विदुषागिरि, वाराणसी से गुजर रही है। 24 से 30 तक बारिश का असर रह सकता है।

प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी आरोपी गिरफ्तार

अमेठी, एजेंसी : जिले के शुकुल बाजार क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कथित अमर्यादित टिप्पणी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि 23 सितंबर की शाम सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी को कथित तौर पर अपशब्द कहे गये हैं।

करंट लगने से दो बहनों और एक कॉलेज छात्रा की मौत

बलिया/सुलतानपुर, एजेंसी : बलिया जिले में बुधवार दोपहर को स्कूल से लौट रही दो बहनों की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि सुलतानपुर जिले में एक अन्य घटना में 22 वर्षीय छात्रा की भी बिजली का झटका लगने से जान चली गई। पुलिस ने बताया कि बलिया में नौवीं कक्षा की छात्रा अंचल यादव (15) और छठी कक्षा में पढ़ने वाली उसकी बहन छात्रा अलका यादव (12), स्कूल से घर लौटते समय जलभराव में उतरे करंट की चपेट में आ गईं।

दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराएगा आईआईटी कानपुर

कानपुर, अमृत विचार : आईआईटी कानपुर दिल्ली में वलाड सीडिंग (कृत्रिम बारिश) कराएगा। इसके लिए आईआईटी कानपुर को डीजीसीए से अनुमति मिल गई है। यह बारिश 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच कराई जाएगी। बारिश के लिए हिंडन एयरपोर्ट से विशेष विमान का उपयोग किया जाएगा। यह विमान वलाड सीडिंग के आकड़ों को भी एकीकृत करेगा।

तीस से अधिक लोगों से 10 करोड़ रुपये की ठगी

ऑनलाइन फ्रॉड: विदेश भागने की फिराक में थे आरोपी

संवाददाता, लखीमपुर खीरी

अमृत विचार: सदर कोतवाली क्षेत्र में 30 से अधिक लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गए, जिसमें मोटे लालच में लगभग 10 करोड़ रुपये डूब गए। पीड़ितों ने शिकायत में बताया कि बॉम्बेटेक एक्सचेंज और बीमैक्स रियल्टी नामक कंपनी ने क्रिप्टो ट्रेडिंग और अन्य योजनाओं में अधिक ब्याज का लालच देकर लोगों से पैसा जमा किया था। पीड़ितों का कहना है कि कंपनी ने हर महीने 7.5% तक ब्याज का वादा कर पैसा जुटाया। शुरुआती महीनों में कुछ निवेशकों को रिफंड मिला, लेकिन जुलाई 2025 के बाद कंपनी ने रिफंड का ऑफ़शन बंद कर दिया। इस पर कई प्रयास करने के बाद पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ। सदर कोतवाली पुलिस ने विदेश भागने की तैयारी कर रहे दो साथियों को पकड़ा है। कोतवाली लाकर उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। ठगे जाने वालों में कुछ बड़े व्यापारी और अधिवक्ता भी शामिल हैं। ठगी के शिकार बने नृपेंद्र कुमार मौर्य, कृष्ण कुमार गुप्ता, लक्ष्मी देवी, विकास कुमार यादव, प्रभात कुमार अवस्थी, श्रीवर्ण श्रीवास्तव अनुराग तिवारी आदि ने सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर

शहर के होटल से पकड़े गए दो टीम लीडर

कंपनी की तरफ से मिली लजरी कार से टीम के दो लीडर लखनऊ से लखीमपुर पहुंचे और वह शहर के एक होटल में रुक कर मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। इस बात की जानकारी जब पीड़ितों को हुई तो तमाम लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों टीम लीडरों को लेकर कोतवाली आई। टीम लीडरों में वीरेंद्र भटनागर और दुर्गा शर्मा का नाम सामने आया है। पुलिस दोनों की दस्तावेज लेकर जांच में जुड़ गई है।

आरोपियों ने पूछताछ कर रही सदर कोतवाली पुलिस

बताया कि कंपनी के मालिक ने खीरी जिले के साथ ही पीलीभीत, शाहजहांपुर और सीतापुर में अपना नेटवर्क फैलाया। पीड़ितों का कहना है कि मालिक एकाध महीने पहले दुबई भाग गया, जबकि टीम लीडरों के माध्यम से वह सीधे संपर्क बनाए रख रहा है और अन्य लोगों को भी ठगी का शिकार बना रहा है। ऑनलाइन ट्रेडिंग और ज्यादा ब्याज के चक्कर में खीर जिले के 30 से अधिक लोगों ने करीब 10 करोड़ रुपये डूबो दिए। कंपनी एक मुश्त जमा हुए रकम पर हर महीने साढ़े सात प्रतिशत ब्याज देने का झांसा देकर यह रकम जुटाई थी। जब रकम रिफंड नहीं हुई तो ठगी की जानकारी हुई। तहरीर में कहा है कि थाना मिर्तौली के गांव राजेपुर निवासी जय प्रकाश मौर्या ने अपने

परीक्षा प्रकरण की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी

देहरादून, अमृत विचार : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की विगत रविवार को सम्पन्न परीक्षा में सामने आई शिकायतों की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पर्यवेक्षण में एसआईटी गठित कर दी गई है, जो एक माह में जांच पूरी करेगी और तब तक आयोग द्वारा परीक्षा के संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुख्य सचिव (सीएस) आनंद बर्द्धन ने बुधवार को बताया कि सरकार के लिए परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुविधा के साथ ही अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरि है। परीक्षा में सामने आई शिकायतों की जांच एसपी देहात ऋषिकेश जया बलूनी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी द्वारा कराई जाएगी।



पीटीआर की माला रेंज स्थित कैप में मौजूद हाथी।

● अमृत विचार

जंगल में आबादी बढ़ने के साथ ही बाध समेत अन्य वन्यजीवों ने जंगल से बाहर निकलकर आबादी क्षेत्रों की ओर दस्तक देनी शुरू कर दी। जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में इजाफा होने लगा। जंगल से बाहर घूम रहे बाघ-तेंदुआ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आक्रामक बाघों से निपटने के लिए हाथियों की कमी खास महसूस की जा रही थी। अक्सर रेस्क्यू ऑपरेशनों के दौरान दुधवा टाइगर रिजर्व से हाथियों को लाया जाता रहा है। ऐसे में देश के अन्य राज्यों से पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हाथियों को लाने की कवायद शुरू हुई, जोकि लंबे अंतराल तक चली।

हमारे पास चरित्र है, हम बिकाऊ माल नहीं : आजम खां

कार्यालय संवाददाता, रामपुर

अमृत विचार : पूर्व मंत्री आजम खां ने बुधवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब अपने चित परिचित अंदाज में दिया। पूरे दिन के इंतजार के बाद वह बुधवार दोपहर आवास से बाहर आए तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। बसपा में जाने के सवाल पर मुस्कान के साथ बोले, हमारे पास चरित्र नाम की चीज है, हम बिकाऊ नहीं हैं यह हमने साबित कर दिया है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रामपुर मिलने न आने के सवाल पर बोले कि बड़ी पार्टी के बड़े



पत्नी तंजीन फात्मा व परिवार के साथ आजम खां।

● अमृत विचार

नेता हैं मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए कोई बात कहेंगे तो उनका बड़प्पन है। पूर्व मंत्री 23 माह के बाद 23 सितंबर को सीतापुर जेल से छूटकर घर पहुंचे। उन्होंने अधिकतर समय परिवार

● बुधवार को पत्रकारों से रुबरु हुए पूर्व मंत्री आजम खां

नहीं रोक सके। जब पूछा गया कि स्थानीय सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी भी उनसे मिलने नहीं आए हैं, इसके जवाब में कहा कि वह खैरियत से रहें आबाद रहें। मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन को लेकर कहा कि मैं अपने यहां टिकट नहीं दिला सका उनका टिकट कैसे कटवा सकता हूं। अखिलेश यादव का कोई फोन आया इस सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें सिर्फ अपनी पत्नी का फोन नंबर याद था उसे भी भूल गए हैं।

नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे

मुख्य संवाददाता, देहरादून

अमृत विचार : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह थामी ने बुधवार को कहा कि राज्य में एक षड्यंत्र के तहत संगठित रूप से नकल जिहाद छेड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनकी सरकार नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाने तक चैन से नहीं बैठेगी। हाल में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय परीक्षा के एक प्रश्नपत्र के तीन पन्ने कथित तौर पर लीक होने से प्रदेश में मचे हड़कंप के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि, युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन मैं उन सभी नकल माफिया और जिहादियों को

युवाओं को हर कीमत पर दिलाएं न्याय : मुख्यमंत्री

सीएम ने कहा कि सभी जानते हैं कि पेपर लीक होने की स्थिति में पेपर शुरू होने से पहले ही बाहर आ जाता है लेकिन इस बार केवल एक जगह एक परीक्षा केंद्र में किसी ने अंदर से फोटो खींचकर बाहर भेज दी, जिस पर बाद में हंगामा खड़ा कर दिया गया। पूरे राज्य में कहीं दूसरी जगह से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जबकि प्रदेश भर में इस परीक्षा में करीब 80 हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया। हम फिर भी उसकी जांच कर रहे हैं, हमारा ध्येय है कि युवाओं को हर कीमत पर न्याय मिले और उन्हें प्रतिभा के आधार पर चयन का अवसर मिलना चाहिए।

बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफिया को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।

रेत खनन के ट्रैक्टर से कुचलकर वृद्ध की मौत

पीलीभीत, अमृत विचार: शारदा नदी से सटे अशोक नगर गांव में खनन के धंधेबाजों ने एक जान ले ली। बाढ़ के बाद खेतों में जमा रेत को उठाने के लिए कुछ धंधेबाज पहुंचे। जब प्रधान पति ग्रामीणों के साथ विरोध के लिए गए तो भगदड़ मच गई। आरोप है कि

खनन में इस्तेमाल ट्रैक्टर ट्राली से कुचलकर एक ग्रामीण की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये भी पता किया जा रहा है कि जानबूझकर ट्रैक्टर से कुचला गया या नहीं। स्थानीय लोगों ने खनन के धंधेबाजों पर कार्रवाई की मांग की है।

ELISTA IS PROUD TO ANNOUNCE THE GST BENEFITS



Smart Cooling, Comfortable Living!

22nd Sept. Onwards

Grab the deals before stock lasts....

Make in India Now in 17+ Countries

LED 32- 7990/- | LED 43 14990/-
UHD 55- 28900/- | UHD 65- 39990/-
UHD 75- 59990/-

Big TV's with Bigger GST Rebate...

AC 1 Ton: 23990/- | Fridge: 10990/-
Washing Machine: 6990/-

ERA RADIOS

Civil Lines, Ayub Khan Crossing, Bareilly
DD Puram Stadium Road, Bareilly
Mob : 8475009751, 8475009727, 8475009759

काशी हिंदू विवि के प्रोफेसर का निलंबन रद्द

प्रयागराज, एजेंसी : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने काशी हिंदू विवि के प्राणि विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर शैल कुमार चौबे का निलंबन रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति सी डी सिंह ने प्रोफेसर चौबे द्वारा दाखल याचिका का निपटारा करते हुए विश्वविद्यालय को इस आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के निलंबन से संबंधित संपूर्ण तथ्य अपनी कार्यवाही में परिलक्षित करके समझ रखने का निर्देश दिया।

यूपी का हुनर, वैश्विक बाजार

खुले समृद्धि के अवसर अपार

उद्घाटन

नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री

द्वारा

25 सितंबर, 2025 प्रातः 9:30 बजे

इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा

गरिमायसी उपस्थिति

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी'

मंत्री, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश

राकेश सचान

मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उत्तर प्रदेश

बुजेश सिंह

राज्य मंत्री, लोक निर्माण, उत्तर प्रदेश

डॉ. महेश शर्मा

सांसद, गौतम बुद्ध नगर

सुरेन्द्र सिंह नागर

सदस्य, राज्य सभा

एवं अन्य गणमान्य महानुभाव

विशेषताएं

- 2,400+ प्रदर्शक
- 1,25,000+ B2B विजिटर
- 4,50,000+ B2C विजिटर
- 75+ देशों की भागीदारी

सहभागी देश-रूस

- बड़े उद्योगों, आई.टी./आई.टी.ई.एस., एम.एस.एम.ई., ओ.डी.ओ.पी., स्टार्टअप, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, संस्कृति, ऊर्जा जैसे सेक्टर के उद्यमियों, विनिर्माताओं और निर्यातकों के लिए वैश्विक मंच
- B2B, B2C, निवेशकों से संवाद के साथ नेटवर्किंग का सुनहरा मौका
- अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से जुड़कर पाएं वैश्विक पहचान • मास्टरक्लास, डेमो, इंडस्ट्री सत्र
- उत्तर प्रदेश के नवाचार, उद्यम और विरासत का प्रदर्शन • सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच

लाइव प्रसारण

DD NEWS व Youtube.com/DDNEWS
Youtube.com/dduttarpradesh

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

काम दमदार डबल इंजन सरकार

नेशनल ब्रीफ

सीईसी को आईआईटी कानपुर का शीर्ष अवाई

नई दिल्ली । मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके शिक्षण संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी-कानपुर) के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार कुमार को कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के ‘उत्कृष्ट पूर्व छात्र’ पुरस्कार से नवाजा गया है। यह संस्थान के पूर्व विद्यार्थियों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। आईआईटी कानपुर से स्विजल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुके कुमार केरल संवर्ग में 1988 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने केरल और केंद्र में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं।

ईडी ने 1.05 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली । ईडी ने कहा कि उसने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे से धन की हेराफेरी के सिलसिले में 1.05 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। यह कारवाई बुधवार को ईडी के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शुरू की गई थी। यह मामला पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के पूर्व वरिष्ठ अनुभागाधिकारी (लेखा) संजय चक्रवर्ती और दो अन्य लोगों पर केंद्रित है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, हमने 22 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएनए), 2002 के प्रावधानों के तहत, भारतीय रेलवे से जुड़े 5.13 करोड़ रुपये के धन शोधन के एक मामले में 1.05 करोड़ मूल्य की चल संपत्ति कुर्क की।

मुर्मू की वृंदावन यात्रा के लिए प्रेसिडेंट स्पेशल

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बृहस्पतिवार सुबह साफ़दरजंग रेलवे स्टेशन से मथुरा के पास वृंदावन रोड स्टेशन तक ले जाने के लिए दुनिया की सबसे शानदार ट्रेन में से एक महाराजा एक्सप्रेस का इस्तेमाल करेगा। यह ट्रेन संदीपों के दौरान उच्च श्रेणी के पर्यटकों के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा संचालित की जाती है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया, 18 डिब्बों वाली इस ट्रेन में महाराजा एक्सप्रेस के 12 डिब्बे होंगे, जिन्में एक प्रेसिडेंशियल सुइट, डीलरस सुइट, रेस्तरां, लाउंज और राष्ट्रपति और उनके कर्मचारियों के लिए पावर कार होंगी।

चार रास सीट के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा की चार सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव 24 अक्टूबर को होंगे। ये सीट 2021 से रिक्त हैं। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को यह जानकारी दी। कार्यक्रम की घोषणा करते हुए, निर्वाचन आयोग ने कहा कि पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू-कश्मीर (विधानसभा सहित) और लद्दाख (विधानसभा रहित) केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है।

असम: जुबिन गर्ग की सीबीआई जांच कराएं

गुवाहाटी, एजेंसी

असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देबब्रत सैकिया ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर प्रसिद्ध गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग की मृत्यु की जांच सीबीआई से कराए जाने का आग्रह किया। गर्ग की पिछले सप्ताह सिंगारपुर में समुद्र में डूबने से मृत्यु हो गई थी।

असम जातीय परिषद और राइजोर दल (आरडी) जैसे अन्य विपक्षी दलों ने भी जुबिन गर्ग की मौत की जांच सीबीआई द्वारा कराए जाने की मांग की है। साथ ही एक

निर्वाचन आयोग ने ई-सत्यापन प्रणाली की शुरू

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग (ईसी) ने मतदाता सूची से नाम हटाने की मांग के प्रावधान का दुरुपयोग रोकने के लिए एक ई-सत्यापन प्रक्रिया शुरू की है। मतदाता सूची से नाम हटाने या शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने वालों को उनके पंजीकृत मोबाइल फोन पर एक बार इस्तेमाल होने वाला पाथवर्ड (ओटीपी) मिलेगा।

एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे मामले हो सकते हैं, जिसमें नाम हटाने की मांग करने वाला व्यक्ति ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराते समय किसी और का नाम या फोन नंबर दे दे। यह अतिरिक्त सुविधा इस प्रकार का दुरुपयोग रोकेंगी। यह सुविधा एक सप्ताह पहले शुरू की गई थी और निर्वाचन अधिकारियों ने कहा था कि यह कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में नामों को हटाने के गलत प्रयासों की प्रतिक्रिया नहीं है।

नेपाल के जेन जी का जिक्र कर सोनम वांगचुक ने भीड़ को उकसाया

केंद्र सरकार ने लगाया आरोप, कहा- लद्दाखी समूहों की बातचीत में प्रगति से राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग खुश नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्र ने बुधवार को आरोप लगाया कि लद्दाख में कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेपाल के जेन जी प्रदर्शन का जिक्र करते हुए दिए गए भड़काऊ बयानों की वजह से भीड़ की हिंसा भड़की और कुछ राजनीति रूप से प्रेरित लोग सरकार और लद्दाखी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में हुई प्रगति से खुश नहीं हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बुधवार को सुबह हुई कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को छोड़कर स्थिति पर शाम चार बजे तक काबू पा लिया गया और सभी से मीडिया और सोशल मीडिया में पुराने और भड़काऊ वीडियो

प्रसारित नहीं करने को कहा गया। बयान में कहा गया है, सरकार पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करके लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर को भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसमें लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी।

बयान में कहा गया है, यह सर्वविदित है कि भारत सरकार 'एपेक्स बॉडी लेह' और 'कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस' के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति और उप-समिति के औपचारिक माध्यम से उनके साथ कई बैठकों की गईं और



लेह में हिंसा से पहले प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर जाम लगाया।

नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की गईं। कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यक्ति इसप्रगति से खुश नहीं हैं और संवाद प्रक्रिया को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि कई नेताओं

द्वारा आग्रह करने के बावजूद, वांगचुक ने

भूख हड़ताल जारी रखी और अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में 'जेन जी' के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया।

राजोआना को अब तक क्यों नहीं दी गई फांसी

करीब 29 वर्षों से जेल में बंद हैं पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह का हत्यारा, केंद्र में लंबित है दया याचिका

नई दिल्ली, एजेंसी

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को पूछा कि 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना को अब तक फांसी क्यों नहीं दी गई। राजोआना पिछले लगभग 29 वर्षों से जेल में बंद है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया को अपराध की गंभीरता से अवगत कराया। पीठ ने नटराज से पूछा, आपने अब तक उसे फांसी क्यों नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कम से कम हमने तो फांसी पर रोक नहीं लगाई है। शीर्ष अदालत राजोआना की दया याचिका पर फैसले में देरी के आधार पर उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की याचिका पर सुनवाई कर रही है। राजोआना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके मुवकिकल की दया याचिका पर कोई फैसला नहीं हुआ है। नटराज ने कहा कि वह निर्देश लेंगे और पीठ को स्थिति से अवगत कराएंगे।

रोहतगी ने कहा, कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि दया याचिका पर समय पर फैसला किया जाना चाहिए। रोहतगी ने कहा, यदि मृत्युदंड को खत्म करना है तो उसे कम किया जाना चाहिए। यदि



सजा कम की जाती है तो वह बाहर आ सकते हैं। रोहतगी ने कहा कि राजोआना एक भारतीय नागरिक हैं और यह भारत-पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने पाया है कि राजोआना ने खुद दया याचिका दायर नहीं की थी, बल्कि यह एक गुरुद्वारा समिति की ओर से दायर की गई है। पीठ ने मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी और कहा कि केंद्र के अनुरोध पर मामले को स्थगित नहीं किया जाएगा।

बीस जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से राजोआना की दया याचिका पर निर्णय लेने को कहा था। केंद्र ने तब मामले की संवेदनशीलता को हवाला देते हुए कहा था कि दया याचिका विचाराधीन है। पिछले साल 25 सितंबर को शीर्ष अदालत ने राजोआना की याचिका पर केंद्र, पंजाब सरकार और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन से जवाब मांगा था।

मृत्युदंड : पीड़ित और समाज केंद्रित दिशानिर्देशों के लिए केंद्र की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड के प्रावधान वाले जघन्य मामलों में पीड़ित और समाज केंद्रित दिशानिर्देश तैयार करने के लिए केंद्र की याचिका पर आठ अक्टूबर को सुनवाई करने का निर्णय लिया। यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। केंद्र ने जनवरी 2020 में शीर्ष अदालत में आवेदन दायर किया था और दलील दी थी कि मौजूदा दिशानिर्देश केवल आरोपी और दोषी केंद्रित हैं। शीर्ष कोर्ट ने 31 जनवरी 2020 को आवेदन की पड़ताल करने पर सहमति जताई थी और विभिन्न हितधारकों से जवाब मांगे थे।

गुमशुदा बच्चों को पता लगाने के लिए केंद्र सरकार को ऑनलाइन समर्पित पोर्टल बनाने का निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुमशुदा बच्चों को पता लगाने और उनसे जुड़े मामलों की जांच पर लगातार निगरानी रखने को गृह मंत्रालय के अधीन समर्पित ऑनलाइन पोर्टल बनाने का केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति बीवी नागरला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इस बात को रेखांकित किया कि खोए बच्चों को पता लगाने में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय का अभाव है। पीठ ने कहा कि प्रत्येक राज्य को पोर्टल के माध्यम से गुमशुदगी की शिकायतों और सूचना के प्रसार के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। कोर्ट ने एक एनजीओ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए।

राज्यों के बार काउंसिल 31 जनवरी 2026 तक

चुनाव कराएं या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि लंबे समय से लंबित राज्य बार काउंसिल के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक करा लिए जाएं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुश्रा और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि एलएलबी प्रमाणपत्रों के लिए सत्यापन अभियान चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता। पीठ ने कहा, हमने बीसीआई की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी राज्य बार काउंसिल के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक करा लिए जाएं।

दंतेवाड़ा में 71

नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा

जिले में 71 माओवादियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है जिनमें से 30 नक्सलियों पर कुल 64 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

माओवादियों के आत्मसमर्पण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि 'डबल इंजन' वाली सरकार 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद का सफाया करने और आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों का पुनर्वास और बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस ने बताया कि बस्तर संभाग में अभियान 'पूना मारगेम' और दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे 'लोन वर्राट्ट' अभियान में 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।

पटना, एजेंसी

कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान तेज करते हुए बुधवार को कथित वोट चोरी, अर्थव्यवस्था, आरक्षण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला और कहा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन के अंत की शुरुआत होगी।

पार्टी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में देश के मुख्य विपक्षी दल ने विदेश नीति को लेकर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'हग्लोमैसी' (गले मिलने की कूटनीति) ने भारत को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग कर दिया है। बिहार प्रदेश कमटी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में चार

पुर्तगाली सरकार से जुड़े 50 वर्ष पुराने भूमि विवाद का निस्तारण

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में एक जमीन को लेकर आधी सदी से अधिक पुराने विवाद का बुधवार को निस्तारण कर दिया। यह भूमि कभी तत्कालीन पुर्तगाली सरकार के पास थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपाकर दत्ता और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने बर्खास्त उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा। पीठ ने अपने 78 पृष्ठ के आदेश में कहा, इस मामले में शायद सबसे अधिक चौकाने वाली बात यह नहीं है कि इस न्यायालय को आधी सदी से भी पहले उत्पन्न हुए विवाद पर निर्णय देने के लिए अनुरोध किया गया है, बल्कि यह और भी बड़ी विडंबना है कि आजादी के 78 साल बाद भी यह न्यायालय औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा प्रदत्त भूमि अधिकारों से उत्पन्न विवाद को सुलझाने में लगा हुआ है, जिन्होंने कभी इस देश की संपत्ति और संसाधनों का शोषण किया था।

लद्दाख का प्रदर्शन कांग्रेस की साजिश का हिस्सा: भाजपा

भाजपा ने आरोप लगाया है कि लद्दाख में हुई हिंसा बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसे हालात पैदा करने की कांग्रेस की साजिश का हिस्सा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संवित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में कहा, लद्दाख में कुछ विरोध प्रदर्शनों को 'जनरेशन जी' के नेतृत्व वाले प्रदर्शन के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन जांच में पाया गया कि यह जनरेशन जी का विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वास्तव में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था। उन्होंने आरोप लगाया, यह कांग्रेस की साजिश है।

वांगचुक ने लेह में हिंसा की घटनाओं पर दुख जताया

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लेह में हुई हिंसा की घटनाओं पर बुधवार को दुख जताया और हिंसा के लिए 'जेन जी' के बीच बढ़ती हताशा को जिम्मेदार ठहराया। वांगचुक ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रदर्शनकारियों में से दो, 72 वर्षीय एक पुरुष और 62 वर्षीय एक महिला को मंगलवार को अस्पताल ले जाया गया था और कहा कि संभवतः यह हिंसक विरोध का तात्कालिक कारण था।



लेह में जलते परिषद सचिवालय भवन के बाहर इकट्ठे लोग।

कांग्रेस ने सहयोगियों से ड्राइविंग सीट लेने को बुलाई सीडब्ल्यूसी बैठक: भाजपा

नई दिल्ली, एजेंसी

भाजपा ने बुधवार को दावा किया कि कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों से ड्राइविंग सीट (निर्णायक भूमिका) अपने हाथ में लेने के लिए बिहार में पार्टी की कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक बुलाई, लेकिन लोग एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को समर्थन देंगे क्योंकि वे लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में भय, अपहरण और भ्रष्टाचार के माहौल को नहीं भूलें हैं।

भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस, जिसने 85 साल के बाद बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है, को यह बताना होगा कि जब राज्य में लोगों का अपहरण हो रहा था, सरकारी धन की वंदरबांट हो रही थी और राजद के शासनकाल में पूरे राज्य में जाति के आधार पर हत्याएं हो रही थीं तब वह मौन क्यों रही? उन्होंने पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे

भाजपाइयों ने कांग्रेस पदाधिकारी को साड़ी पहनाई

टाणे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छेड़छाड़ की हुई तस्वीर साझा करने के आरोप में टाणे में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर एक कांग्रेस पदाधिकारी को सार्वजनिक रूप से साड़ी पहना दी। भाजपा के एक स्थानीय पदाधिकारी ने मंगलवार को इस कृत्य का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस पदाधिकारी मामा उर्फ प्रकाश पगारे द्वारा प्रधानमंत्री को बदनाम करने के प्रयास के जवाब में ऐसा किया गया था। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। पगारे (72) ने कहा कि वह मंगलवार को इस कृत्य में शामिल भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

आरक्षण की 50 फीसदी सीमा तोड़ेंगे : राहुल गांधी पटना। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि देश में आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को तोड़ा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान पर लगातार हमला हो रहा है और पूरे देश में लोगों के हक छीने जा रहे हैं। यहां 'अतिपिछड़ा न्याय संकल्प' जारी करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, न्याय संकल्प में जो 10 घोषणाएं की गई हैं, उनकी गारंटी मेरी है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा में उन्होंने दो बातें रखी थीं-पहली, सामाजिक न्याय के लिए 50 फीसदी आरक्षण की दीवार को तोड़कर फेंक दिया जाएगा तथा दूसरी, देश में पिछड़े, अतिपिछड़े और दलितों को उचित भागीदारी नहीं मिली है, इसके लिए जाति-जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने डर कर जाति-जनगणना की बात मान ली है। गांधी ने कहा कि यह संकल्प अतिपिछड़ों की आवाज है और इसे लागू किया जाएगा।

में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महासचिव केशी वेणुगोपाल, जयप्रम रमेश और कई अन्य नेता शामिल हुए। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के अध्यक्षत्व होने के कारण वह और उनकी पुत्री प्रियंका गांधी वाद्रा बैठक में शामिल नहीं हो सकीं। सूत्रों का कहना है कि कार्य समिति के सदस्य शशि थरूर भी अस्वस्थ

होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने दावा किया कि भाजपा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है और अब उन्हें बोझ मानने लगी है। खरगे ने ट्रंप के ताजा बयानों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष किया।

अध्ययन

राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पत्रिका प्रोसीडिंग्स में प्रकाशित निष्कर्षों में जताई गई गंभीर चिंता

जैसे हाल के दशकों में सूखी गंगा, वैसा पहले कभी नहीं हुआ

नई दिल्ली, एजेंसी

गंगा नदी के जल प्रवाह के 1300 वर्ष के रज़ाओं के विश्लेषण पर आधारित एक अध्ययन में कहा गया है कि पिछले कुछ दशकों में इस नदी में जलधारा सूखने की जो प्रवृत्ति देखी गई है, वह इस नदी घाटी में जीवन बसर कर रहे लाखों लोगों पर भीषण और अभूतपूर्व प्रभाव डाल सकती है।

राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पत्रिका 'प्रोसीडिंग्स' में प्रकाशित निष्कर्षों में कहा गया है कि जलधारा सूखने के दौरान प्रवृत्ति '1991 से 2020 तक देखने को मिली वैसी पिछली सहस्राब्दी से पहले देखने



को नहीं मिला। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर और अमेरिका के एरिजोना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गंगा के सूखने का संबंध दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितंबर) के दौरान कम वर्षा से जोड़ा है। दल ने 1991-2020 के दौरान उपकरणों, ऐतिहासिक

अभिलेखों और जल प्रवाह के मॉडल के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग किया और पिछले 1,300 वर्षों (700-1990 ई.) के जल प्रवाह मॉडल का पुनर्निर्माण किया।

अध्ययन के लेखकों ने कहा, 60 करोड़ से अधिक लोगों के

लिए महत्वपूर्ण गंगा नदी घाटी में जलधारा के प्रवाह में गंभीर और अभूतपूर्व कमी की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जिससे जल और खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। दल ने पाया कि 1990 के दशक से गंगा नदी जल प्रवाह के सूखने की जो प्रवृत्ति लगातार लम्बे काल से देखी गई, इसकी तुलना 16वीं शताब्दी में इसी तरह जलधारा सूखने से की जा सकती है किंतु मौजूदा प्रवृत्ति पिछली प्रवृत्ति की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक विकट है।

अध्ययन में कहा गया कि 1951-2020 के दौरान वार्षिक स्तर पर वर्षा में 9.5 प्रतिशत की

उल्लेखनीय गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जिसमें भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 30 प्रतिशत से अधिक की अधिक गिरावट देखी गई है। लेखकों ने कहा कि भले ही जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा में वृद्धि होने की संभावना है, फिर भी हिंद महासागर में तेजी से बढ़ रही गर्मी तथा उपमहाद्वीप में कम होती गर्मी के कारण उत्तर भारत में मानसून कमजोर हो गया है। इसमें कहा गया कि कम वर्षा के कारण भूजल का स्तर नहीं बढ़ पा रहा है। साथ ही सिंचाई के स्रोतों के तेजी से कम होने के कारण गंगा जल प्रवाह के सूखने से उत्पन्न स्थिति और विकट हो सकती है।

सरकार का ऐतिहासिक कदम

जातिगत भेदभाव भारतीय समाज की सबसे जटिल और पुरानी समस्याओं में से एक रहा है। संविधान ने समानता का अधिकार देकर सभी नागरिकों को एक समान दर्जा प्रदान किया, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जाति का उल्लेख, भेदभाव और उससे उपजे तनाव लगातार मौजूद रहे। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यह निर्देश जारी किया है कि अब पुलिस दस्तावेजों, सरकारी कार्याहियों, एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, शव परीक्षण रिपोर्ट, तलाशी मेमो या किसी भी तरह के अधिकारिक दस्तावेजों में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, राजनीतिक रैलियों, सार्वजनिक मंचों और शिकायतों में भी जाति का नाम जोड़ना प्रतिबंधित होगा। यह कदम केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि समाज में जातिगत विषमता को मिटाने की दिशा में एक ठोस पहल है। जाति का उल्लेख कई बार कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालता है। किसी अपराध के आरोपी या पीड़ित की जाति लिखे जाने से सामाजिक तनाव भड़क सकता है। पुलिस रिकॉर्ड्स में जाति अंकित करने से एक वर्ग विशेष की छवि हमेशा के लिए अपराध से जुड़ जाती है, जिससे सामाजिक न्याय की मूल भावना को ठेस पहुंचती है। सरकार का यह निर्णय इस कुशथा को समाप्त करने और सभी नागरिकों को समान दर्जा देने का प्रयास है। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाली जाति-आधारित नारेबाजी और भड़काऊ संदेशों पर भी सख्त निगरानी रखने की बात कही गई है।

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब समाज को धीरे-धीरे जाति की जकड़न से बाहर लाने की जमीन तैयार होगी। जब किसी सरकारी दस्तावेज में जाति अंकित नहीं होगी, तो धीरे-धीरे लोगों की सोच से भी यह भेदभाव मिटने लगेगा। प्रशासनिक स्तर पर यह एक साहसी कदम है, क्योंकि इससे न केवल पुलिस और प्रशासनिक कार्यवाहियों में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों में यह संदेश जाएगा कि राज्य सबको समान दृष्टि से देखता है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि केवल दस्तावेजों से जाति हटाने भर से सामाजिक समरसता स्थापित हो जाएगी।

राजनीतिक दलों को भी इस कदम से सबक लेना होगा। चुनावी रैलियों और भाषणों में जाति-आधारित गोलबंदी हमारी लोकतांत्रिक संस्कृति पर धब्बा है। यदि ऐसे उल्लेख समाप्त होंगे तो राजनीति का ध्यान असल मुद्दों-रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की ओर जाएगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसे स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि यह निर्णय जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम है। यह सही भी है, क्योंकि जब तक जाति की दीवारें बरकरार हैं, तब तक वास्तविक समानता संभव नहीं है। आखिरकार, यह निर्णय केवल प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि सामाजिक सुधार की ओर बढ़ता हुआ संदेश है। यदि इसे सख्ती से लागू किया गया और राजनीतिक-सामाजिक संगठनों ने भी सहयोग किया, तो आने वाले वर्षों में भारतीय समाज जातिगत बंधनों से बहुत हद तक मुक्त हो सकता है।

प्रसंगवश

बदलता समाज और खत्म होता बचपन

आधुनिकता के इस युग में दुनिया जैसे-जैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बूते स्मार्ट होती जा रही है, वैसे-वैसे वह अपना कुछ खोती भी जा रही है ! आधुनिकता की चकाचौंध में हम क्या खो रहे हैं, इसका आभास भी नहीं है। भारत सहित दुनिया भर में मासूम बच्चे, जो ठीक से बोल भी नहीं पाते, वह स्मार्ट फोन आपरेट करना सीख जाते हैं। वह स्मार्ट फोन से क्या-कुछ सीख रहे हैं, इसका माता-पिता को आभास भी नहीं है। आधुनिक दौर का यह बचपन स्मार्ट फोन की तरह दिनों-दिन अपडेट हो रहा है। यह बच्चे माता-पिता की कल्पना से भी आगे की बात करने लगा है। इन बच्चों के कार्य-व्यवहार को जब करीब से देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनका बचपन समय से पहले ही चला गया है। यह अपनी उम्र से कहीं अधिक बड़ों जैसा

व्यवहार करते नजर आते हैं। बचपन मानव जीवन का सबसे सुंदर और सर्वोत्तम दौर होता है। न कोई फ़िक्र न कोई चिंता और न कोई जिम्मेदारी। बचपन सदा मस्तमौला होता है और बचपन में जीवन निर्माण का खाका तैयार होता है, जिसमें भविष्य गढ़ा जाता है। समाज जैसे-जैसे बदलता जा रहा है, उसका असर भी बच्चों पर पड़ रहा है। इन सबके बीच बचपन गुम हो रहा है। आज मानव के पास अथाह दौलत और शोहरत है। बड़ी-बड़ी इमारतें हैं और इन इमारतों में आधुनिक विलासिता की वह सारी चीजें मौजूद हैं, जिनके बूते जीवन ऐशो-आराम से जिया जा सकता है ! इन इमारतों के दरवाजों में बच्चों को एक तरह से कैद कर दिया गया है। ज्यादातर बच्चों के हाथों में स्मार्ट मोबाइल थमा दिया गया है। मोबाइल से यह बच्चे वह सब कुछ सीख रहे हैं, जो उनकी उम्र के लिहाज से काफी बुरा है। यहां तक कि बच्चों की पहुंच अश्लील सामग्री तक हो जा रही है। इससे बच्चों का मन-मस्तिष्क दूषित हो रहा है। कच्ची उम्र में उन्हें यह सब कुछ बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। खराब बात यह है कि मां-बाप को इसका अंदाजा भी नहीं है कि उनका बच्चा मोबाइल पर कैसी सामग्री देख रहा है?

अपने देश में बच्चों के लिए कोई रीति-नियम नहीं बचा है। न कोई सामाजिक मानक ही तय किए गए हैं। कोविड में आन लाइन क्लासेज के जरिए एक बार जग यूकली बच्चों के हाथ मोबाइल लगा तो वह फिर उनसे नहीं छूटा। बात सिर्फ अश्लील सामग्री तक ही नहीं है, अब ज्यादातर बच्चे स्कूल की कितानों की जगह यूट्यूब से पढ़ना पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब पर मौजूद कोर्स की हर सामग्री अपडेटेड या सही हो, यह जरूरी नहीं है। वहां से पढ़ा बच्चा जब एजमा में गलत जवाब लिखकर आता है और मास्स कम आते हैं तो मां-बाप जान ही नहीं पाते कि कमी कहां पर रह गई। वह यही कहते मिलते हैं कि उनके बच्चे ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी, जाने कैसे उसके नंबर कम आए हैं !

नई पीढ़ी में नैतिकता हो, वह भविष्य में समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सके, इसकी जिम्मेदारी समाज के साथ ही मां-बाप की भी है। मासूम अपने बचपन को इंज्याय कर सकें और वह अपनी उम्र के हिसाब से धीरे-धीरे ज्ञान अर्जित करें, यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से मस्तिष्क का विकास होता है, उसी तरह की जानकारी भी उनके दिमाग में जानी चाहिए। कच्ची उम्र में बड़ों की बातें सीख जाना उनके लिए खतरनाक है और यह उन्हें गलत दिशा में ले जाएगा। ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं, जहां बच्चों ने मोबाइल देखकर क्राइम करना सीखा। बच्चों का भविष्य सुंदर हो और वह अपने बचपन को बेहतर जी सकें, यह जिम्मेदारी सभी की है।



प्रतिबद्धता के क्षण में, ब्रह्मांड आपकी सहायता करने के लिए षड्यंत्र रचता है।

–जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे, जर्मन दार्शनिक

‘ब्रेन ड्रेन’ को ‘ब्रेन गेन’ में बदलने का अवसर



डॉ. शिवम भारद्वाज
असिस्टेंट प्रोफेसर, जिएएल विश्वविद्यालय

किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी भौतिक संपत्तियों या प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, बल्कि उसकी मानव संसाधन क्षमता से भी निर्धारित होती है। विशेषकर तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में यह अकाट्य सत्य रूप में प्रकट होता है। अमेरिका ने पिछले तीन-चार दशकों में जिस गति से स्वयं को वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित किया है, उसमें विदेशी प्रतिभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन वैली की सफलता में अहम योगदान दिया है। यही कारण है कि H-1B वीजा को अमेरिका और भारत के बीच एक सेतु के रूप में देखा जाता है।

प्रतिवर्ष हजारों भारतीय इस वीजा के माध्यम से अमेरिका जाते हैं, अपनी जिंदगी संवारते हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं, लेकिन अब बड़ा अवरोध खड़ा हो गया है। ट्रंप ने घोषणा की कि एन-H-1B वीजा आवेदकों से \$100,000 का एकमुश्त शुल्क लिया जाएगा। यह राशि इतनी अधिक है कि अधिकांश पेशेवरों के लिए अमेरिका की राह मुश्किल होने वाली है। यह निर्णय केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि वैश्विक प्रतिभा प्रवाह को रोकने की एक कोशिश है, हालांकि यह नीति केवल नए आवेदकों पर लागू होती है, मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं। फिर भी प्रश्न यह है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? अमेरिका और भारत दोनों के लिए इसका क्या अर्थ होगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह नीति अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित होगी और भारत के लिए अवसर का द्वार खोलेगी?

कई रिपोर्टरों के अनुसार अमेरिका में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित (STEM) पेशेवरों की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध नौकरियों के सापेक्ष उपलब्धता सीमित है। इस कमी को अब तक विदेशी प्रतिभा पूरी करती रही है। भारतीय पेशेवर अकेले H-1B वीजा धारकों का 70% से अधिक हिस्सा रखते हैं, लेकिन अब

\$100,000 की बाधा के चलते तमाम योग्य पेशेवर अमेरिका जाने का सपना छोड़ देंगे। आईटी दिग्गजों के लिए भी चिंता यही है कि उन्हें काम करने के लिए सही लोग नहीं मिलेंगे अथवा खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अध्ययनों से साबित हुआ है कि विदेशी प्रतिभा स्थानीय नौकरियां छीनती नहीं, बल्कि पैदा करती हैं। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन की यह नीति घरेलू श्रमिकों को खुरा करने के नाम पर विदेशी प्रतिभा के दरवाजे लगभग बंद कर रही है। इसका परिणाम होगा धीमी नवाचार गति, उत्पादन में गिरावट और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना।

अब बात भारत की। सबसे बड़ा नुकसान भारतीय पेशेवरों को होगा। अमेरिका लंबे समय से भारतीय पेशेवरों, खासकर आईटी क्षेत्र के लिए ‘करियर डेस्टिनेशन’ रहा है। बेहतर वेतन, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और स्थायी निवास की संभावना ने लाखों युवाओं को वहां खींचा, लेकिन इस नई नीति ने इस रास्ते को लगभग असंभव बना दिया है। इसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक भी है। कई परिवार टूटेंगे, कई सपने अधूरे रह जाएंगे। भारतीय आईटी कंपनियों के लिए भी यह झटका है। तमाम कंपनियां वर्षों तक अपने कर्मचारियों को H-1B के जरिए अमेरिका भेजकर प्रोजेक्ट्स संभालती रहीं। अब यह मॉडल बेहद महंगा होता जा रहा है। छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए तो यह शुल्क विनाशकारी साबित होगा।

तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका में मुश्किलें बढ़ने का अर्थ है कि भारतीय प्रतिभा अब देश के भीतर ही अवसर ढूंढने को प्रयासरत होगी। पहले जिन युवाओं के लिए अमेरिका ही करियर की मंजिल था, वे अब भारत में अवसर ढूंढेंगे। यही भारत के लिए ‘ब्रेन ड्रेन’ को ‘ब्रेन गेन’ में बदलने का अवसर है। भारत में पहले से ही 1,580 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) मौजूद हैं, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना रिसर्च, डेवलपमेंट और

सपोर्ट का काम भारत से करवाती हैं। 2030 तक इनकी संख्या 2,300 से अधिक होने का अनुमान है। इससे लाखों नई नौकरियां और अरबों डॉलर का निवेश भारत में आ सकता है। भारतीय स्टार्टअप इको सिस्टम पहले से ही दुनिया के अग्रणी ईको सिस्टम्स में से एक है। अगर बेहतरीन इंजीनियर और वैज्ञानिक यहीं रुकते हैं, तो स्टार्टअप्स की संख्या में बढ़ोत्तरी भी संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत वैश्विक नेतृत्व हासिल कर सकता है।

यह नीति केवल भारत और अमेरिका का मामला नहीं, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा से भी जुड़ी है। चीन अपनी STEM शिक्षा और रिसर्च पर भारी निवेश कर रहा है। यूरोप और कनाडा जैसी जगहें भी भारतीय प्रतिभा को आकर्षित करने में सक्रिय हैं। यदि अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए तो यह प्रतिभा कहीं और जाएगी। सवाल यह है कि भारत इस मौके को पकड़ पाएगा या नहीं? शिक्षा और कौशल विकास में निवेश, शोध को प्रोत्साहन, कर ढांचे में सुधार, स्टार्टअप्स को पूंजी और सरन नियम तथा वैश्विक कंपनियों को स्थिर माहौल, ये सब मिलकर भारत को प्रतिभा का असली घर बना सकते हैं।

भारत के लिए यह कठिनाई भी है और अवसर भी। कठिनाई इसलिए कि हजारों भारतीय पेशेवरों के सपने टूटेंगे और आईटी कंपनियों के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, लेकिन अवसर इसलिए कि यही प्रतिभा अब भारत की धरती पर रहकर देश के उद्योग, स्टार्टअप और शोध को मजबूत करेगी। अगर भारत सरकार और उद्योग जगत मिलकर सही रणनीति अपनाते हैं तो बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, नवाचार के लिए अनुकूल माहौल और वैश्विक मानकों के अनुरूप वेतन संरचना की बंदौलत भारत के लिए आर्थिक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। सवाल यह नहीं कि अमेरिका ने क्या खोया, बल्कि यह है कि भारत क्या हासिल करता है।



भारतीय सिनेमा फाल्के से मोहनलाल तक

नई दिल्ली का विज्ञान भवन 23 सितंबर को भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम क्षण का गवाह बना। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के करहमलों से मलयालम सिनेमा के महानायक मोहनलाल को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान ‘दादासाहेब फाल्के पुरस्कार’ प्रदान किया गया। यह क्षण केवल एक अभिनेता की उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की विविधता, उसकी कलात्मकता और उसके वैश्विक प्रभाव का प्रतीक भी था। दक्षिण भारतीय सिनेमा की परंपरा और गौरव को नए शिखर पर ले जाने वाले मोहनलाल ने अपने चार दशक लंबे अभिनय करियर में न केवल मलयालम बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का परचम लहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहनलाल को इस सम्मान पर बधाई देते हुए कहा कि उनका सफर न केवल एक अभिनेता की कहानी है, बल्कि यह भारतीय सिनेमा की विविधता, जीवंतता और वैश्विक पहुंच का भी प्रतीक है। यह टिप्पणी इस तथ्य को रेखांकित करती है कि मोहनलाल केवल एक फिल्म स्टार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गर्व के दूत भी हैं।

मोहनलाल विश्वनाथन, जो दक्षिण भारत में ‘मोहनलाल’ के नाम से विख्यात हैं, का जन्म 21 मई 1960 को केरल में हुआ था। 1978 में ‘थिरुनट्रुम’ नामक फिल्म से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई, लेकिन वास्तविक पहचान उन्हें 1980 के दशक के मध्य में मिली, जब वे मलयालम सिनेमा के नए चेहरे के रूप में स्थापित हुए। चार दशकों से अधिक के इस सफर में मोहनलाल ने 400 से अधिक फिल्मों में काम करते हुए दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी और मलयालम सिनेमा को नई पहचान दिलाई।

मोहनलाल की अभिनय शैली को ‘नेचुरल एक्टिंग’ का पर्याय माना जाता है। चाहे साधारण मध्यवर्गीय युवक की भूमिका हो, ऐतिहासिक चरित्र हो या एक्शन हीरो मुर्मु के करहमलों से मलयालम सिनेमा के महानायक मोहनलाल को भारतीय सिनेमा का ‘द कंफ़लीट एक्टर’ कहा जाता है। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में ‘किरिडम’ (1989), ‘भारत’ (1991), ‘वानप्रस्थम’ (1999), ‘दृश्यम’ (2013, 2021), ‘इरुपथम नूट्टांडी’ और ‘पुलिमुगन’ (2016) शामिल हैं। ‘वानप्रस्थम’ ने तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की और कांस फिल्म महोत्सव में भी प्रदर्शित हुई, जबकि ‘दृश्यम’ को हिंदी तथा अन्य भाषाओं में रीमेक किया गया।

मोहनलाल का अभिनय सफर केवल लोकप्रियता तक सीमित नहीं रहा बल्कि उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले। वे पांच बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी प्रतीक है। यह टिप्पणी इस तथ्य को रेखांकित करती है कि मोहनलाल केवल एक फिल्म स्टार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गर्व के दूत भी हैं।

मोहनलाल विश्वनाथन, जो दक्षिण भारत में ‘मोहनलाल’ के नाम से विख्यात हैं, का जन्म 21 मई 1960 को केरल में हुआ था। 1978 में ‘थिरुनट्रुम’ नामक फिल्म से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई, लेकिन वास्तविक पहचान उन्हें 1980 के दशक के मध्य में मिली, जब वे मलयालम सिनेमा के नए चेहरे के रूप में स्थापित हुए। चार दशकों से अधिक के इस सफर में मोहनलाल ने 400 से अधिक फिल्मों में काम करते हुए दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी और मलयालम सिनेमा को नई पहचान दिलाई।

की शुरुआत हुई थी, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार उन व्यक्तित्वों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने सिनेमा को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने में आजीवन योगदान दिया हो। पहली बार यह पुरस्कार देविका रानी को मिला था और तब से लेकर अब तक यह पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर, सत्यजीत रे, दिलीप कुमार, लता मंगेशकर, अशोक कुमार, राजकपूर, अम्मानोरमल्लिनी, रुजानाकांत और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों को मिल चुका है।

मोहनलाल का सम्मान दर्शाता है कि दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग (मलयालम, तमिल, तेलुगू और कन्नड़) ने वैश्विक स्तर पर भारतीय फिल्मों की पहचान को मजबूत किया है। भारतीय सिनेमा पर अक्सर बॉलीवुड का दबदबा चर्चा में रहता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोहनलाल इस परंपरा के ऐसे स्तंभ हैं, जिन्होंने मलयालम सिनेमा को न केवल भारत के हर कोने तक पहुंचाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान दिलाया। उनकी फिल्मों में सामाजिक यथार्थ, पारिवारिक भावनाएं, आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है।

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त कर मोहनलाल ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय सिनेमा की आत्मा उसकी विविधता और कलात्मकता में निहित है। कुल मिलाकर, मोहनलाल को मिला दादासाहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा की उस यात्रा का उत्सव है, जो दादासाहेब फाल्के की पहली फिल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’ से शुरू हुई और आज वैश्विक मंचों तक पहुंच चुकी है।

सोशल फोरम

‘मिरर लाइफ’ के खतरे

दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच मिरर लाइफ यानी ऐसी जीवन संरचना, जिसमें जीवों के सारे अणु उल्टे (mirrored) हों, पर चल रहे रिसर्च को रोकने की मांग तेज हो गई है। विश्व भर के 38 प्रमुख वैज्ञानिकों ने 2024 के अंत में Science जर्नल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि मिरर बैक्टीरिया मानव, जानवरों, पौधों और पूरे पर्यावरण के लिए

गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसी तरह से ऐसे उल्टे-जैसे बैक्टीरिया लैब से बाहर आ जाएं, तो पृथ्वी पर कई जीवों की पूरी आबादी के लिए वास्तव में कोई बचाव तंत्र ही नहीं रहेगा, क्योंकि अब तक हमारे इन्फ़्यून सिस्टम सिर्फ प्राकृतिक (मूल) जैविक अणुओं को पहचानने के लिए विकसित हुए हैं।

मिरर लाइफ प्रयोगशाला में बनाई जाने वाली जीवन की ऐसी व्यवस्था है, जिसमें जीवन के सभी अणु, जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन अपने प्राकृतिक रूप के ठीक उल्टे यानी दर्पण-छवि (mirror image) जैसे होते हैं। जैसे हर इंसान के दाएं और बाएं हाथ की बनावट एक जैसी है, लेकिन एक-दूसरे की दर्पण छवि है, वैसे ही मिरर लाइफ के अणु भी सामान्य जीवन के अणुओं के ठीक विपरीत होते हैं।

धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवों में डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स दाहिने (right-handed) होते हैं और प्रोटीन के अमीनो एसिड्स बाएं (left-handed) होते हैं। मिरर लाइफ में ये बिलकुल उल्टे होंगे। डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बाएं और अमीनो एसिड्स दाहिने होंगे। ऐसा जीवन अब तक धरती पर कहीं नेचुरली नहीं मिला है। वैज्ञानिक सिंथेटिक जीव विज्ञान की मदद से इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह अभी सिर्फ प्रयोगशाला की कल्पना है। चिंता यह है कि अगर ऐसे मिरर जीव बन जाते हैं, तो इन्हें पहचानना, रोकना या नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली इन्हें नहीं पहचान पाएगी।

मई 2025 में मैनचेस्टर में वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं और नैतिक विशेषज्ञों की अहम बैठक हुई थी। इसमें अधिकांश विशेषज्ञों ने माना कि मिरर लाइफ पर रिसर्च बंद करना जरूरी है, ताकि ऐसी संरचनाएं न बनाई जा सकें, जिन्हें रोकना न जा सके। यह भी कहा गया कि जो रिसर्च दवाओं में मिरर इमेज अणुओं का इस्तेमाल करती है, वह अलग और सुरक्षित हैं, क्योंकि ये पहले ही FDA द्वारा अनुमोदित दवाओं में प्रयोग हो रहे हैं।

–फैसबुक वाल से



सामयिकी

यूपीएस में कर्मचारी नहीं दिखा रहे हैं रुचि

केंद्रीय सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के चयन करने की तारीख 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी थी। यूपीएस जो देश में पहली अप्रैल 2025 से लागू की गई थी। यह तारीख इसलिए बढ़ानी पड़ी, क्योंकि यूपीएस के चयन में अभी तक काफी कम कर्मचारियों ने रुचि दिखाई है। कर्मचारी ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग काफी पहले से करते आ रहे हैं, दूसरी ओर यूपीएस के चयन में इनकी दिलचस्पी कम आंकी जा रही है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में तब्दील किए गए कर्मचारी यूपीएस में जाने से गुरेज कर रहे हैं।

लाभभग 24 लाख कर्मचारियों में से कुल 40,000 कर्मचारियों ने ही अभी तक यूपीएस के चयन की स्वीकृति दी है, जो संख्या में बहुत कम है। यही मुख्य कारण है कि केंद्र सरकार ने यूपीएस के विकल्प के लिए तिथि को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी यूपीएस चुनने का विकल्प केंद्र द्वारा दिया जा रहा है। अब बात करते हैं ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की। ओपीएस, एनपीएस के पूर्व में प्रदान की जानी वाली पेंशन स्कीम है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन से इसके लिए किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की जाती थी, अथवा अंशदान नहीं लिया जाता था, जबकि सरकार ही पूरी राशि प्रदान किया करती थी। सरकार पेंशन की गारंटी देती थी और मूल वेतन के साथ-साथ डीए का 50% हिस्सा कर्मचारियों की पेंशन के लिए दिया जाता था।

एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम पहली जनवरी 2004 से लागू की गई थी। इस स्कीम में ओपीएस की तुलना में रात-दिन का फर्क देखने को मिला। नतीजन, कर्मचारियों का 10 प्रतिशत अंशदान और सरकार का 14 प्रतिशत अंशदान इस स्कीम में शामिल किया गया। इस अंशदान के बाद राशि को बाजार आदि में निवेश किया जाना प्रस्तावित हुआ। बस यहीं से मानों कर्मचारियों ने एक जंग सी छेड़ दी। कर्मचारी ओपीएस की मांग सरकार से करने लगे। मूलतः एनपीएस बाजार नियंत्रित रिटर्न्स पर निर्भर रहने वाली स्कीम है, जिसमें रिस्क फैक्टर बने रहने के चॉंस भी हैं। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीच का रास्ता निकाल कर यूपीएस स्कीम को लांच किया। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है, जहां पर अंशदान के साथ-साथ पेंशन की गारंटी भी प्रदान की जाएगी।

अब बात करते हैं यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। यहां साफ करना होगा कि यूपीएस एक वैकल्पिक स्कीम है यानी एनपीएस की तरह इसे अपनाना जरूरी नहीं है। यूपीएस का चयन कर्मचारियों को अपने हिसाब से करना है। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है। चूंकि यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस का एक समावेशी पहलू है, इसलिए यूपीएस एक महत्वपूर्ण योजना हो सकती है, जहां सुरक्षा भी मिले वह भी गारंटी के साथ। यूपीएस में म्यानतम 25 वर्ष की सेवा उपरांत कर्मचारी को उसके अंतिम 12 माह के मूल वेतन का 50 प्रतिशत, पेंशन व्यवस्था के तौर पर सुनिश्चित किया गया है। वहीं 10 वर्ष की सेवा उपरांत 10,000 मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है। ग्रेजुएटी एवं डीए भुगतान का विकल्प भी समायोजित किया गया है, जबकि अंशदान की बात करें तो इसमें कर्मचारी के मूल वेतन और डीए का 10 प्रतिशत व सरकार द्वारा भी कर्मचारी के मूल वेतन और डीए का 10 प्रतिशत अंशदान शामिल किया गया है। इसके साथ ही अतिरिक्त 8.5 प्रतिशत यूपीएस पूल कॉर्पस भी सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। यानी सरकार का योगदान लगभग 18.5 प्रतिशत तक रहेगा।

ब्रह्मांड हमेशा से इंसानों के लिए रहस्यमयी रहा है। रात के अंधेरे में टिमटिमाते तारे, चमकता चांद और ग्रहों की अनोखी दुनिया हर किसी को आकर्षित करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रहस्यों को समझने के लिए एक खास विज्ञान है- एस्ट्रोफिजिक्स। अगर आप विज्ञान और गणित के छात्र हैं और अंतरिक्ष की गुंतियों को सुलझाने का सपना देखते हैं, तो एस्ट्रोफिजिक्स आपके करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है। यह न केवल तारों और ग्रहों का अध्ययन करता है, बल्कि हमें बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, वह कैसे बदलता है और भविष्य में कैसा होगा।

रोमांच से भरा करियर

- रहस्यमयी विषयों से जुड़ाव- यह आपको यूनिवर्स की सबसे गहरी पहलियों से रूबरू कराता है।
- इन्वोल्वेशन और रिसर्च- इसमें रिसर्च का दायरा बहुत बड़ा है। आप नई खोजों में योगदान दे सकते हैं।
- वैज्ञानिक करियर - इस क्षेत्र में करियर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसरों से भरा है।
- प्रेरणादायक कार्यक्षेत्र- अंतरिक्ष एजेंसियों, रिसर्च संस्थानों और विश्वविद्यालयों में काम करने का मौका मिलता है।

कौन कर सकता है ये कोर्स

- एस्ट्रोफिजिक्स में एडमिशन लेने के लिए 12 वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स (पीसीएस) से पास होना चाहिए। इसके साथ ही छात्रों को कम से कम 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा होने अंक होना चाहिए।

एंट्रेंस एग्जाम

- आईआईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट (आईएटी)- भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान
- एसईएसटी- नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट
- जेईई एडवांस्ड - जॉईंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस्ड
- सीयूईटी-यूजी - कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट

इन संस्थानों से कर सकते हैं कोर्स

- भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु।
- राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर।
- उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद।
- भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद।
- हर्ष चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज।
- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु।
- टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई।
- अंतर- विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी केंद्र पुणे।
- आर्यभट्ट प्रेक्षणीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान नैनीताल।
- रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु।



सितारों और ग्रहों की रहस्यमयी दुनिया में बनाएं भविष्य

क्या है

एस्ट्रोफिजिक्स

- एस्ट्रोफिजिक्स खगोलशास्त्र और भौतिकी का मिश्रण है। इसमें वैज्ञानिक ब्रह्मांड के हर छोटे-बड़े पहलू का अध्ययन करते हैं। इसमें हम अध्ययन करते हैं कि तारे कैसे जन्म लेते और खत्म होते हैं। ग्रह और उपग्रह अपनी कक्षाओं में कैसे चलते हैं। ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार और डार्क मैटर क्या होता है। ब्रह्मांड किनाड़ा बड़ा है और समय के साथ कैसे फैल रहा है। इस विज्ञान में दूरबीन, उपग्रह और गणित का इस्तेमाल होता है। आजकल हबल और जेम्स वेब जैसी दूरबीनें ब्रह्मांड की तस्वीरें भेजती हैं, जिससे वैज्ञानिक नई खोज कर पाते हैं।



इस फील्ड में करियर

- एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं:
- रिसर्च संस्थानों और प्रयोगशालाओं में रिसर्च साइंटिस्ट
- इसरो, नासा, ईएसए जैसी स्पेस एजेंसियों में स्पेस साइंटिस्ट
- डेटा एनालिस्ट खगोलीय और कॉस्मिक डेटा को समझने व विश्लेषण करने के लिए।
- सॉफ्टवेयर और कम्प्यूटेशनल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध के लिए सिमुलेशन तैयार करना।
- एयरोस्पेस एंड टेलीकॉम सेक्टर- उपग्रह और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में
- साइंस लेखक या पत्रकार- विज्ञान को सरल भाषा में आम जनता तक पहुंचाने के लिए।

सैलरी

- एस्ट्रोफिजिस्ट की सैलरी अनुभव, जगह और काम के प्रकार के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। एक फ्रेशर एस्ट्रोफिजिस्ट को लगभग 4-6 लाख रुपये सालाना मिल सकता है, जबकि अनुभवी फ्रेशर को 8-15 लाख रुपये तक का सालाना पैकेज हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में इससे भी ज्यादा हो सकती है।

जॉब अलर्ट

एसएससी कांस्टेबल भर्ती

- पद का नाम : कांस्टेबल
- कुल पद- 7565
- योग्यता- 12 वीं
- अंतिम तिथि- 21/10/2025
- वेबसाइट- <https://ssc.gov.in/>

केनरा बैंक अपरेंटिस भर्ती

- पद का नाम : अपरेंटिस
- कुल पद- 3500
- योग्यता- स्नातक
- अंतिम तिथि- 12/10/2025
- वेबसाइट- <https://nats.education.gov.in/>

इंडियन बैंक भर्ती

- पद का नाम : स्पेशलिस्ट ऑफिसर
- कुल पद- 171
- योग्यता- स्नातक (बीटेक/बीई/ एमबीए आदि)
- अंतिम तिथि- 13/10/2025
- वेबसाइट- <https://ibpsreg.ibps.in/ibabase25/>

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) भर्ती

- पद का नाम : शिक्षण और गैर शिक्षण
- पद- 7267
- योग्यता- पदानुसार
- अंतिम तिथि- 23/10/2025
- वेबसाइट- <https://nests.tribal.gov.in/>



यूकेपीएससी प्रधानाचार्य भर्ती 2025

- पद का नाम : प्रधानाचार्य
- कुल रिक्तियां : 692
- योग्यता- पदनुसार
- अंतिम तिथि : 12-10-2025
- ऑनलाइन वेबसाइट : ukpscnet.in

आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नया ट्रेंड तेजी से सामने आ रहा है। हाल ही में यह ट्रेंड युवा पीढ़ी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये तस्वीरें नब्बे के दशक की हीरोइनों जैसी हैं। यंगस्ट्स अपनी तस्वीरों को सोशल प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से एडिट करवाकर शेयर कर रहे हैं। कभी फिल्मी पोस्टर जैसी, कभी किसी फैंटेसी वर्ल्ड की झलक जैसी तो कभी बेहद आकर्षक अंदाज में दिखाई देती हैं। इस ट्रेंड ने यूजर्स में नई ऊर्जा भर दी है और हर दूसरा व्यक्ति अपनी एडिटेड फोटो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर साझा करता दिखाई दे रहा है। कुछ माह पहले भी हमें ऐसा ही एक ट्रेंड देखने को मिला था- गिबली आर्ट का, जिसमें लोग अपनी तस्वीरों को कार्टून में बदल रहे थे। तकनीक अब केवल सुविधाओं तक सीमित नहीं रही, अब यह भावनाओं को भी छू रही है। एआई एडिटिंग का जादू



ऐसा है कि लोग अपनी तस्वीरों को कुछ पल के लिए नए और मनचाहे रूप में देखकर खुश हो रहे हैं। जिन लोगों ने हमेशा खुद को किसी खास अंदाज में देखने की कल्पना की थी, एआई ने उन्हें साझा करता दिखाई दे रहा है। कुछ माह पहले भी हमें ऐसा ही एक ट्रेंड देखने को मिला था- गिबली आर्ट का, जिसमें लोग अपनी तस्वीरों को कार्टून में बदल रहे थे। तकनीक अब केवल सुविधाओं तक सीमित नहीं रही, अब यह भावनाओं को भी छू रही है। एआई एडिटिंग का जादू

महसूस कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी का खतरा भी एक अलग चिंता का विषय बना हुआ है। कुल मिलाकर, एआई एडिटेड फोटो का यह ट्रेंड मनोरंजन और तकनीकी अनुभव का एक नया जरिया है। यह लोगों को थोड़े समय के लिए उत्साह और खुशी देता है, लेकिन लंबे समय में इसका आकर्षण फीका पड़ सकता है इसलिए इसे केवल प्रयोग और मनोरंजन की दृष्टि से देखना ही बेहतर है। वैसे भी असली सुंदरता हमेशा हमारी वास्तविकता, आत्मविश्वास और स्वभाव में ही छिपी रहती है।

लेखिका

रीता मटियाली

ट्यूशन पढ़ाकर स्टार्टअप के लिए जुटाया पैसा

रोजी मैन्डौलिया के स्टार्टअप की कहानी। जिसे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने स्वर्ण पदक देकर डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया। रोजी एकेटीयू की बीटेक की मेधावी छात्रा हैं। आइए आपको बताते हैं कि रोजी मैन्डौलिया के स्टार्टअप की कहानी, उन्होंने अपना करियर कैसे शुरू किया और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा।



कैसे शुरू करें स्टार्टअप

अब युवाओं का उद्यमी बनना मुश्किल नहीं है। बहुत से युवा उद्यमिता (इंटरप्रेन्योरशिप) में आना चाहते हैं, लेकिन अक्सर सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि शुरुआत कैसे करें? मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपके पास एक आइडिया है और उसमें एक भी डिफ्रेंशिएटर (यानी कोई अलग या अनोखी चीज) है, तो बिना डरे शुरुआत करें। मैं स्वयं टियर- 2 और टियर- 3 शहरों के छात्रों और युवाओं को प्रशिक्षण देती हूँ कि "कैसे बिना किसी पूंजी के सिर्फ एक आइडिया से शुरुआत की जा सकती है।" जो भी युवा इस राह पर चलना चाहता है, वह मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं- Instagram: @thirdeye_shop, Email: support@thirdeyeshop.in से आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं।

इतने अच्छे काम की इतनी कम कीमत क्यों मिल रही है।

मैं वापस लौटकर इस मुद्दे पर सोचना शुरू किया और जरूरी जानकारीयों को इकट्ठा करना शुरू की। मुझे समझ आया कि सबसे अधिक शोषण हैंड एम्ब्रॉयडरी कारीगरों का हो

रहा है। किसी को 32 रुपये तो किसी को 50 रुपये मुश्किल से प्रतिदिन मिलते हैं, लेकिन यह तो इनकी मेहनत और हुनर का शोषण है। मैंने ठान लिया कि मुझे उनके लिए कुछ करना है। उस समय मुझे सामने दो रास्ते थे। एक बीटेक के शोषण हैंड एम्ब्रॉयडरी कारीगरों का हो

स्कॉलरशिप बनाएगी पहचान, बैंक पूरी करेगा सपनों की उड़ान



सपने बड़े हैं, पढ़ाई कर कुछ बनने की लालक है। ऐसे में बजट की कमी के चलते पढ़ाई में बाधा आ रही है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकारी सहायता से इतर कई गंभीर मेधावियों को स्कॉलरशिप प्रदान करती है। इन स्कॉलरशिप के जरिए मेधावी अपने खुली आंखों से देखे गए सपनों को पूरा कर सकते हैं। बैंकों की ओर से दी जाने वाली स्कॉलरशिप स्कूल और कॉलेज स्तर तक की पढ़ाई करने वाले मेधावियों के लिए होती है। कई ऐसी विशेष स्कॉलरशिप भी यह बैंक ऐसी प्रदान करते हैं, जो युवाओं को तकनीकी शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए होती है।

उत्तीर्ण कर चुकी मेधावी छात्राएं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रुपये हैं, उन्हें सुविधा प्रदान की जाती है। स्कॉलरशिप के तहत छात्राओं को 1,50,000 तक की स्कॉलरशिप प्रतिवर्ष, जो ग्रेजुएशन में गंभीर मेधावियों को स्कॉलरशिप प्रदान करती है। इन स्कॉलरशिप के जरिए मेधावी अपने खुली आंखों से देखे गए सपनों को पूरा कर सकते हैं। बैंकों की ओर से दी जाने वाली स्कॉलरशिप स्कूल और कॉलेज स्तर तक की पढ़ाई करने वाले मेधावियों के लिए होती है। कई ऐसी विशेष स्कॉलरशिप भी यह बैंक ऐसी प्रदान करते हैं, जो युवाओं को तकनीकी शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए होती है।

एसबीआई आशा स्कॉलरशिप

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) अपनी 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप' प्रदान कर रहा है। इस स्कॉलरशिप के तहत, छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बैंक की ओर से स्कूल के छात्रों के लिए खासतौर पर कक्षा 6 से 8 तक 15 हजार रुपये तक की सहायता की जा रही है। इसी तरह कक्षा 9 से 12 तक के लिए 20 हजार रुपये तक की स्कॉलरशिप दिए जाने का प्रावधान है। कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट 40 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप बैंक द्वारा दी जाती है। इसी तरह आईआईटी छात्रों के लिए 2 लाख व आईआईएम छात्रों के लिए 5 लाख से 20 लाख तक (विदेश में पढ़ाई के लिए) की सहायता दी जाती है।

एचडीएफसी बैंक स्कॉलरशिप

एचडीएफसी बैंक भी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करता है, जिसे एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएसएस स्कॉलरशिप कहा जाता है। इस स्कॉलरशिप के तहत, छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कॉलरशिप के लिए कक्षा 1 से 6 तक 15 हजार रुपये। कक्षा 7 से 12, डिप्लोमा, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए 18 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसी तरह स्नातक (सामान्य कोर्स) 30 हजार रुपये व स्नातक (व्यावसायिक कोर्स) 50 हजार रुपये मिलते हैं। उधर स्नातकोत्तर (सामान्य कोर्स) 35 हजार रुपये व स्नातकोत्तर (व्यावसायिक कोर्स) 75 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए पिछली परीक्षा में कम से कम 55 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए।

मॉडल और आमदनी

- थर्डआई का मॉडल "वर्क-प्रॉम-होम" है। हम कारीगरों को सामग्री उपलब्ध कराते हैं, 50 प्रतिशत एडवांस देते हैं और प्रोडक्ट तैयार होने के बाद शेष भुगतान करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि महिलाएं अपने घरों से अपने समय के अनुसार काम कर सकें। हमारे प्रोडक्ट की कीमत का लगभग 70-75 प्रतिशत हिस्सा सीधे कारीगरों को दिया जाता है।

पुरस्कार और उपलब्धियां

- डब्लूडब्लूफ स्क्रीनरलैंड में 75 वैश्विक कंपनियों में चयन।
- स्टार्टअप महाकुंभ में डीयूसी सेक्टर का विजेता एक लाख रुपए पुरस्कार।
- सी राईजेज कांक्लेव में 21,000 रुपए का पुरस्कार।
- राज्यापाल आनंदीबेन पटेल और भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला द्वारा "सर्वश्रेष्ठ महिला छात्र-नेतृत्व स्टार्टअप" का सम्मान मिला।
- सुलक्षणा सावंत गोवा की मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी की पदमिनी फाउंडेशन के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- थर्डआई से कानपुर और दिल्ली के गांवों की लगभग 82 महिलाएं जुड़ी हैं। पहले तो महिलाएं केवल 50 रुपया प्रतिदिन कमाती थीं, अब वे 500 रुपए से अधिक प्रतिदिन कमा रही हैं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी सफलता है कि जब कोई कारीगर आत्मसम्मान से कहता है कि वह अपने परिवार की रीढ़ है। मैं धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ और मानती हूँ कि मेरी कामयाबी में भगवान शिव की कृपा, माता-पिता के आशीर्वाद और कारीगर बहनों के विश्वास के कारण ही संभव हो पाया है।

लेखक: मार्कण्डेय पांडेय

	बाजार	संसेवस ↓	निफटी ↓
	बंद हुआ	81,715 .63	25,056.90
	गिरावट	386.47	112.60
	प्रतिशत में	0.47	0.45

बरेली मंडी

वनस्पति तेल तिलहन : तुलसी 2575, राज श्री 1820, फ़ॉर्बुन कि. 2220, रविन्द्रा 2530, फ़ॉर्बुन 13 किग्रा 1950, जय जवान 1960, सफ़िन 2020, सुरज 1960, अवसर 1880, उजाला 1920, गुहणी 13 किग्रा 1880, क्लासिक (किग्रा) 2095, मोर 2160, चक्र टिन 2330, ब्लू 2110, आशीर्वाद मस्टर्ड 2455, स्वास्तिक 2530

किराना (प्रतिकु .) : हल्दी निजामाबाद 14000, जीरा 24000, लाल मिर्च 14000-17000, धनिया 9000-11000, अजवायान 13500-20000, मेथी 7000-8000 सौंफ 9000-13000, सोंठ 27000, (प्रतिक .) लोंग 800-1000, बादाम 780-1080, काजू 2 पीस 880, किसमिस पीली 300-400, मखाना 800-1100

चावल (प्रति कु .) : डबल चाबी सेला 9600, साइस 6500, शरबती कच्ची 4950, शर्बती स्टीम 5100, मंसूरी 4000, महबूब सेला 4050, गौरी रॉयल 7300, रालभोग 6850, हरी पत्ती (1- 5 किग्रा) 10100, हरी पत्ति नेचुरल 9100, जैनेथ 8100, गलैकरी 7400, सुमो 4000, गोल्डन सेला 7900, मंसूरी पनसट 4350, खुरजा 4300

दाल दलहन : मूंग दाल इंदौर 9800, मूंग धोवा 10000, राजमा चित्रा 12800-13500, राजमा भूतान नया 10100, मलका मोटी 7250-7450 मलका दाल 7550-8900, मलका छौंटी 7550, दाल उड़द बिलासपुर 8000-9000, मसूर दाल छेटी 9500-11200, दाल उड़द दिल्ली 10300, उड़द साबुत दिल्ली 9900, उड़द धोवा इंदौर 12800, उड़द धोवा 10000-11000, चना काला 7050, दाल चना 7450, दाल चना मोटी 7600, मलका विदेशी 7300, रूपकिशोर बेसन 8200, चना अकोला 7200, डबरा 7200-9200, सच्चा हीरा 8700, मोटा हीरा 10700, अरहर गोला मोटा 7700, अरहर पटका मोटा 8100, अरहर कोरी मोटा 8800, अरहर पटका छोटा 9800-10300, अरहर कोरी छेटी 10300

चीनी : डालमियां 4500, पीलीभीत 4400, सितारगंज 4360, धामपुर 4500

बिजनेस ब्रीफ

फोनपे ने आईपीओ के लिए सौंपे दस्तावेज

नई दिल्ली | डिजिटल भुगतान प्रदाता फोनेपे ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के समक्ष दस्तावेज दाखिल किए हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि फोनेपे लिमिटेड ने ‘प्री-फाइलिंग’ गोपनीय मार्ग से आईपीओ के लिए सेबी के समक्ष दस्तावेज दाखिल किए हैं। प्रवक्ता ने आईपीओ के आकार का खुलासा करने से इन्कार कर दिया।

वीएमएस का शेयर बढ़त के साथ सूचीबद्ध

नई दिल्ली | टीएमटी बार विनिर्माता वीएमएस टीएमटी का शेयर अपने निर्गम मूल्य 90 रुपये से छह प्रतिशत की बढ़त के साथ बुधवार को बाजार में सूचीबद्ध हुआ। बीएसई पर शेयर ने निर्गम मूल्य से छह प्रतिशत की बढ़त के साथ 105 रुपये पर शुुरुआत की। एनएसई में यह 5.95 प्रतिशत की बढ़त के साथ 104.90 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 500.78 करोड़ रुपये रहा। वीएमएस टीएमटी के आईपीओ को गत शुक्रवार को अंतिम दिन 102.26 गुना अभिदान मिला था।

मुहूर्त महोत्सव : 5 मिनट में बिके ओला के सारे वाहन

नई दिल्ली | देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के ‘मुहूर्त महोत्सव’ में ग्राहकों का उत्साह देखने को मिला। कंपनी ने बुधवार को बताया कि बिक्री शुरू होने के सिर्फ पांच मिनट के भीतर ही उसके सारे वाहन बिक गए। यह भारी मांग ओला द्वारा हाल ही में शुरू किए उत्सव अभियान की वजह से आई है।

आयातित क्रेन पर डंपिंग रोधी शुल्क की सिफारिश

नई दिल्ली | वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने चीन से आयातित कुछ क्रेनों के आयात पर पांच साल के लिए डंपिंग- रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को सरसे आयात से बचाना है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने जांच में निष्कर्ष निकाला है कि उत्पाद को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत में निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है। डीजीटीआर ने कहा कि पांच साल की अवधि के लिए निश्चित डंपिंग- रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।

एथनॉल उत्पादन के लिए शर्तों में दी ढील

नई दिल्ली | सरकार ने बुधवार को दूसरी पीढ़ी के एथनॉल के निर्यात के लिए अतिरिक्त नीतिगम शर्तों को अधिसूचित किया। यह एथनॉल खोई, लकड़ी के कचरे और औद्योगिक कचरे जैसे सामग्रियों से उत्पादित किया जाता है। इसका उत्पादन खोई, लकड़ी के कचरे, लिग्नोसेल्यूलोसिक फीडस्टॉक (कृषि और वानिकी अवशेष जैसे चावल और गेहूँ के भूसरे, मक्का) जैसी सामग्रियों और गंधक, शैवाल जैसे गैर-खाद्य फसलों के जरिये होता है।

	बाजार	संसेवस ↓	निफटी ↓
	बंद हुआ	81,715 .63	25,056.90
	गिरावट	386.47	112.60
	प्रतिशत में	0.47	0.45

	सोना- 1,17,600 प्रति 10 ग्राम
	चांदी- 1,37,300 प्रति किलो

अमृत विचार

बरेली, गुरुवार , 25 सितंबर 2025

www.amritvichar.com

केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण ने की जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की शुरुआत, दिसंबर से होगी सुनवाई करदाताओं के लिए न्याय का सच्चा प्रतीक जीएसटीएटी

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की शुरुआत की। यह कंपनियों और कर विभाग के बीच विवादों के त्वरित निपटारे का मार्ग प्रशस्त करेगा।

सीतारमण ने कहा कि जीएसटीएटी के सक्रिय होने के साथ ही कंपनियां इसके पोर्टल पर अपने मामले दायर कर पाएंगे और दिसंबर से अपीलीय न्यायाधिकरण में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने जीएसटीएटी को ‘करदाताओं के लिए न्याय का सच्चा प्रतीक’ बताते हुए कहा कि 2017 में जीएसटी की शुरुआत के साथ एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की जो परिकल्पना की गई थी, अब उसमें एक और आयाम जुड़ गया है। यह मंच व्यवसायों के लिए भरोसे का स्तंभ और भारत की निरंतर आर्थिक वृद्धि का उत्प्रेरक बनेगा। जीएसटी से संबंधित करीब 4.83 लाख लंबित मामलों को इस पोर्टल पर स्थानांतरित किया जाएगा। सरकार ने अपील दाखिल करने की समय-सीमा 30 जून, 2026 तक बढ़ा दी है। पुराने विवादों को प्रार्थमिकता के आधार पर लिया जाएगा ताकि मामलों का बोझ नियंत्रित ढंग से निपटया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटीएटी



जीएसटीएटी का शुभारंभ करती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साथ में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी।

निष्पक्ष विवाद निवारण की गारंटी

सीतारमण ने कहा कि जीएसटीएटी की स्थापना करदाताओं के लिए न केवल अनुपालन और रिफंड को सरल बनाने का हिस्सा है, बल्कि यह निष्पक्ष और कुशल विवाद निवारण की गारंटी भी है। यह सुधारों का एक स्वाभाविक विस्तार है। जब कोई करदाता विवाद की स्थिति में आता है तो वह कर प्रशासन के समक्ष पहली अपील कर सकता है। दूसरे स्तर पर वह केंद्र या राज्य के आदेशों के खिलाफ जीएसटीएटी में अपील कर सकेगा।

न्यायिक और तकनीकी सदस्य किए गए नियुक्त

सरकार ने हाल ही में जीएसटीएटी के विभिन्न खंडपीठों के लिए न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की है। मई 2024 में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय कुमार मिश्रा को प्रधान पीठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगस्त, 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मयंक कुमार जैन को जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण की प्रधान पीठ का न्यायिक सदस्य बनाया गया। इसके अलावा सेवानिवृत्त आईएसएस अधिकारी ए. वेणु प्रसाद और सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता को तकनीकी सदस्य नियुक्त किया गया था।

केवल अपीलीय मंच ही नहीं, बल्कि अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की भूमिका भी निभाएगा। इससे करदाताओं को कार्यवाही शुरू होने से पहले और बाद दोनों स्तरों पर व्यापक समाधान उपलब्ध होंगे।

राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि यह न्यायाधिकरण कर विवादों में एकरूपता, अनुमान-योग्य परिणाम और अपील प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा।

अमेरिका के साथ ऊर्जा व्यापार बढ़ने की उम्मीद

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- ऊर्जा सुरक्षा ऐसा क्षेत्र जहां हम सभी को मिलकर काम करना होगा

न्यूयॉर्क, एजेंसी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश को आने वाले वर्षों में ऊर्जा उत्पादों के क्षेत्र में अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों में अमेरिका की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। दुनिया मानती है कि ऊर्जा सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम सभी को मिलकर काम करना होगा। भारत ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी है, हम अमेरिका सहित दुनिया भर से ऊर्जा के बड़े आयातक में से एक हैं।

केंद्रीय मंत्री ने न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास, यूएस-इंडिया स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) और भारत के अग्रणी कार्बन मुक्त समाधान प्रदाता ‘रीन्यू’ द्वारा आयोजित कार्यक्रम ‘बदलते वैश्विक परिदृश्य में ऊर्जा सुरक्षा: सीमाओं के पार लचीले ऊर्जा बाजारों का निर्माण’ में मुख्य भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में ऊर्जा उत्पादों पर अमेरिका के साथ हमारा व्यापार बढ़ेगा।

घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार होने के नाते हमारे ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों



● **बोले- अमेरिका सहित दुनिया भर से ऊर्जा के बड़े आयातक में से एक है भारत**

द्विपक्षीय समझौते पर निष्कर्ष को न्यूयॉर्क गए गोयल

कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव पंकज जैन, यूएसआईएसपीएफ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं अध्यक्ष मुकेश अग्नि, रीन्यू की सह-संस्थापक वैशाली निगम सिन्हा और रीन्यू के चेयरमैन एवं सीईओ सुमंत सिन्हा शामिल हुए। गोयल द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर शीघ्र निष्कर्ष निकालने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। वह अमेरिकी पक्ष के साथ बैठकों के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

में अमेरिकी भागीदारी अधिक होगी जिससे भारत के लिए मूल्य स्थिरता, ऊर्जा के विविध स्रोत सुनिश्चित होंगे और हमें ऊर्जा एवं उससे परे विभिन्न

मोच्चों पर अमेरिका के साथ असौमित संभावनाओं को खोलने में मदद मिलेगी। गोयल ने कहा कि एक और क्षेत्र जहां भारत और अमेरिका मिलकर

से छुटकारा मिलेगा। एनआईपीएल के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ रितेश शुक्ला ने कहा कि यह साझेदारी यूपीआई की वैश्विक स्वीकृति बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क बनाने की दिशा में अहम कदम है।

एनआईपीएल देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली का संचालन करने वाली कंपनी एनपीसीआई की अनुपंगी है। क्यूएनबी के समूह मुख्य व्यवसाय अधिकारी यूसूप महमूद अल-नीमा ने कहा कि इस पहल से भारतीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी और कतर के खुदरा एवं पर्यटन क्षेत्र को भी फायदा होगा। इस सुविधा की शुरुआत से स्थानीय व्यापारियों को ज्यादा ग्राहक मिलेंगे और डिजिटल लेनदेन बढ़ेगा।



● **एनआईपीएल ने कतर नेशनल बैंक के साथ मिलकर की सुविधा की शुरुआत**

सुविधा का इस्तेमाल करने वाले प्रतिष्ठान हैं। धीरे-धीरे यह अन्य प्रमुख पर्यटक स्थलों और बाजारों में उपलब्ध होगी। कतर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों में भारतीय यात्री दूसरे स्थान पर हैं। नई सुविधा से उन्हें लकदी रखने और मुद्रा बदलने

मुंबई, एजेंसी

जीएसटी सुधारों से कारोबारी वृद्धि को मिलेगी गति

जीएसटी सुधार का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह व्यापार सुगमता को बढ़ावा देगा, खुदरा कीमतों को कम करेगा और उपभोग वृद्धि को मजबूत करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बुधवार को जारी बुलेटिन में यह बात कही गई।

बुलेटिन अनुसार, प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर अमेरिकी शुल्क लगाने और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की राजकोषीय स्थिति को लेकर नई चिंताओं से वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है। आरबीआई के सितंबर बुलेटिन में अर्थव्यवस्था की स्थिति

कारोबार

टैक्स ऑडिट एक वित्तीय अनुशासन

टैक्स ऑडिट एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे आयकर विभाग द्वारा लागू किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्ति या व्यवसाय अपनी वास्तविक आय और कर देनदारी को सही तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें वित्तीय लेनदेन, बही-खाते और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाती है। टैक्स ऑडिट का मुख्य उद्देश्य कर चोरी और कर अपवंचना पर रोक लगाना है। यह प्रक्रिया न केवल सरकार के कर राजस्व को बढ़ाती है बल्कि व्यवसायों और व्यक्तियों को वित्तीय अनुशासन में रहने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इससे पारदर्शिता और ईमानदारी का माहौल बनता है।

क्यों है जरूरी

टैक्स ऑडिट आयकर विभाग द्वारा की जाने वाली एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि व्यवसाय या व्यक्ति सही तरीके से अपनी आय घोषित करें और उचित कर अदा करें। यह जांच केवल कर चोरी को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने का भी एक साधन है।

टैक्स ऑडिट की प्रक्रिया

● **चयन/ नोटिस** : आयकर विभाग किसी व्यवसाय या व्यक्ति का चयन टैक्स ऑडिट को करता है। चयनित व्यक्ति/व्यवसाय को वित्तीय दस्तावेज पेश करने का निर्देश देता है।

● **जांच/ रिपोर्ट तैयार** : बही-खाते, लेनदेन और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच होती। जांच के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें अनियमितता का उल्लेख होता है।

कारोबार

कंपनियों को दो माह में उत्पादों की कीमतों में पूर्ण समायोजन का भरोसा

नई दिल्ली, एजेंसी

जीएसटी की कम दरें लागू होने के साथ रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों को उत्पादों के लिए कम कीमतें तय करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें दो महीने में इसके पूर्ण समायोजन की उम्मीद है। रोजमर्रा के उपयोग वाली वस्तुएं बनाने वाली (एफएमसीजी) कंपनियों ने उत्पाद के मूल्य दो, पांच और 10 रुपये तक कम किए हैं।

उद्योग जगत के विशेषज्ञों के अनुसार, कंपनियों के पास गैर-मानक कीमतें अपनाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है क्योंकि उनके पास चीजों का वजन (ग्रामेज) तेजी से बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, जिसके लिए कारखाने के ढांचे में बदलाव की जरूरत होती है। अस्थायी तौर पर उन्होंने सरकारी निर्देशों का पालन करने के लिए लोकप्रिय मूल्य पैक की अधिकतम खुदरा कीमत कम कर दी है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दो स्तरीय पांच और 18 प्रतिशत दरें 22 सितंबर से प्रभावी

जीएसटी 2.0

● **एफएमसीजी कंपनियों ने उत्पाद के मूल्य दो, पांच और 10 रुपये तक किए हैं कम**

हैं। पारले प्रोडक्ट्स के उपाध्यक्ष मयंक शाह ने कहा कि यह पूरी तरह अस्थायी है। आम तौर पर जब भी आप किसी बदलाव या ऐसी किसी चीज की बात करते हैं, तो पैक के वजन में बदलाव करते हैं। इस तरह की चीजों में डेढ़ से दो महीने लगते हैं। अक्टूबर और नवंबर के रैंपर छप चुके हैं। अब बाहर जाकर वजन में बदलाव करना और एमआरपी स्थिर रखना मुश्किल है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अबनीश रॉय ने कहा कि ये एफएमसीजी कंपनियां द्वारा अल्पकालिक उपाय हैं। कंपनियां अपने सामान का वजन बढ़ाएंगी और दो, पांच और 10 रुपये के मूल्य पर वापस आ जाएंगी क्योंकि 4.5 या 4.6 रुपये के मूल्य व्यावहारिक नहीं हैं। डाबर के सीईओ मोहित मल्होत्रा ने कहा कि हमने अपने पैक की कीमतों में समायोजन किया है।

आरबीआई बुलेटिन के अनुसार, अमेरिकी शुल्क और नई चिंताओं से वैश्विक अनिश्चितता

बैंकों के पर्यवेक्षी एसडीक्यूआई में सुधार

आरबीआई ने कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का पर्यवेक्षी आंकड़ा गुणवत्ता सूचकांक (एसडीक्यूआई) जून में सुघरकर 89.9 हो गया, जबकि मार्च 2025 में यह 89.3 था। आरबीआई ने एसडीक्यूआई बनाया है जो रिटर्न जमा करने में आंकड़ों की सटीकता, समयबद्धता, पूर्णता और निरंतरता को मापता है। इस सूचकांक का उद्देश्य पर्यवेक्षी रिटर्न दाखिल करने पर आरबीआई के मास्टर निर्देश 2024 में बताए गए सिद्धांतों के पालन का आकलन करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के एसडीक्यूआई स्कोर में मार्च 2025 की तुलना में जून 2025 में सुधार हुआ है।

अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय मजबूती दिखायी है। यह घरेलू कारकों की वजह से 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान पांच-तिमाहियों की उच्च आर्थिक वृद्धि दर

निवेशक संपत्ति के संरक्षकों के लिए सेबी ने बदले नियम

नई दिल्ली, एजेंसी

बाजार नियामक सेबी ने संरक्षकों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ यानी शुद्ध संपत्ति की शर्त को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये कर दिया है। इसका उद्देश्य संरक्षकों के जोखिम प्रबंधन तंत्र को मजबूत करना है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने कहा कि मौजूदा संरक्षकों को शुद्ध संपत्ति संबंधी नए प्रावधानों को पुरा करने के लिए तीन साल का समय मिलेगा। संरक्षक निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा और रखखाव के जिम्मा संभालने वाला व्यक्ति या संस्था होता है। यह निवेशक के शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड एवं अन्य निवेशों को सुरक्षित रखने के साथ उसके खाते का सही रिकॉर्ड भी रखता है। सेबी ने 18 सितंबर को जारी अधिसूचना में कहा कि जिस संरक्षक को 2025



● **विनियम बोर्ड ने नए प्रावधानों को पूरा करने के लिए दिए तीन साल**

के संशोधित नियम लागू होने से पहले पंजीकरण प्रमाणपत्र मिल चुका है, उसे तीन साल में अपनी शुद्ध संपत्ति कम से कम 75 करोड़ रुपये तक बढ़ानी होगी। यह शर्त हर गतिविधि के लिए अलग-अलग लागू होगी। सेबी ने संरक्षकों के लिए कई जिम्मेदारियां भी तय की हैं। इनमें उपयुक्त संचालन ढांचा, जोखिम प्रबंधन नीतियां, तकनीकी क्षमता व ढांचागत क्षमता हैं। सेबी ने संरक्षकों को अनुचित प्रतिसंस्था से बचने और ग्राहकों या अन्य संरक्षकों को नुकसान पहुंचाने से रोकने का निर्देश भी दिया है।



